राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण सोमवार 16 फरवरी 2026 वर्ष-9,अंक-24 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

भारत की तेल कंपनियां अपने सर्वोत्तम हित को समझेंगी और उसी आधार पर फैसले लेंगी

-जयशंकर ने अमेरिका को साफ शब्दों में समझाया

नई दिल्ली। रूसी तेल आयात कम करने की प्रतिबद्धता वाले दावे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और ऊर्जा खरीद पर फैसला राजनीतिक दबाव के बजाय लागत, जोखिम और उपलब्धता द्वारा निर्देशित होंगे। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के साथ एक संवादात्मक सत्र में जयशंकर ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा बाजार जटिल है और भारत की तेल कंपनियां अपने सर्वोत्तम हित में जो उचित समझेगी, उसके आधार पर निर्णय लेंगी। उन्होंने कहा कि रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति हमारा दृढ़ संकल्प है क्योंकि यह हमारे इतिहास और विकास का अभिन्न अंग है। यह एक ऐसा गहरा संबंध है जो राजनीतिक परिदृश्य से परे है। ऊर्जा के मुद्दों की बात करें तो, आज यह एक जटिल बाजार है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि भारत में तेल कंपनियां, यूरोप की तरह और शायद दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह, उपलब्धता, लागत और जोखिमों को ध्यान में रखकर ऐसे निर्णय लेती हैं जो उनके हित में हों। क्या भारत व्यापार समझौते के प्रावधानों के तहत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा और क्या इस कदम से नई दिल्ली की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर असर पड़ सकता है। भारत ने वाशिंगटन के इस दावे की न तो पुष्टि की है और न ही खंडन किया है कि उसने रूसी कच्चे तेल की खरीद बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच हाल ही में हुई फोन वार्ता के बाद, दोनों पक्षों ने भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ में अहम कमी की घोषणा की, जिससे यह पहले के 50 फीसदी से घटकर 18 फीसदी हो गया। इस कमी में वह 25 फीसदी टैरिफ हटाना भी शामिल है जो ट्रम्प ने पिछले साल भारत पर लगाया था। उन्होंने इस दंडात्मक टैरिफ का कारण नई दिल्ली द्वारा रूस से तेल की निरंतर खरीद बताया था।

सिक्किम और त्रिपुरा में लगे भूकंप झटके, तीव्रता कम होने से नहीं हुआ जान-माल का नुकसान

-भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में भी हिली धरती, बड़े नुकसान की खबर नहीं

नई दिल्ली। रविवार सुबह भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में भूकंप के कई झटके लगे। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल चार झटके दर्ज किए गए, जिनमें से तीन सिक्किम और एक त्रिपुरा में आया। सिक्किम के नामची में सुबह 5ः26 बजे और फिर 6ः58 बजे 2.4 तीव्रता के दो झटके महसूस किए गए, जबकि मंगन में सुबह 5ः10 बजे 2.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसके साथ ही त्रिपुरा के गोमती जिले में भी सुबह 6ः38 बजे 2.6 तीव्रता का झटका आया। राहत की बात यह है कि इन झटकों की तीव्रता कम थी और केंद्र जमीन से केवल 5 से 10 किलोमीटर की गहराई में था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में सुबह 4ः28 बजे 4.3 तीव्रता का सबसे तेज झटका महसूस आया, जिससे वहां हल्के नुकसान की खबरें है, हालांकि किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। इसके अलावा म्यांमार में तड़के दो बार 3.2 तीव्रता के झटके लगे। अमेरिका के ओक्लाहोमा, इंडोनेशिया के जावा, चिली और पुर्तगाल के अजोरेस द्वीप समूह में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सीस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक पुर्तगाल में आए भूकंप की तीव्रता 2.6 मापी गई। विशेषज्ञों के मुताबक रविवार को आए इन झटकों से कहीं भी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। सिक्किम और त्रिपुरा में आए भूकंप के झटके हल्के थे, जिनसे जनजीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। हालांकि, वैश्विक स्तर पर भूकंप हमेशा एक बड़ी चिंता का विषय है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया भर में भूकंपों के कारण हर साल औसतन 40 से 60 अरब डॉलर यानी करीब 3 से 5 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है। 2011 में जापान का तोहोकू भूकंप और 2023 में तुर्की-सीरिया में आई तबाही इसके भयावह उदाहरण हैं।

चंडीगढ़ को मिली इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, पीएम मोदी ने दिखाई वर्चुअली हरी झंडी

चंडीगढ़। चंडीगढ़ के लोगों को रविवार को 25 नई इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मिला है। इन बसों को पीएम मोदी ने गुवाहाटी से वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है। ये बसें चंडीगढ़ को पीएमई बस सेवा योजना के तहत मिली हैं। इस दौरान चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद थे। प्रशासन का लक्ष्य अप्रैल तक शहर में कुल 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का टारगेट पूरा करना है। चंडीगढ़ के प्रशासन गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इन बसों के आने से शहर के यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन लोगों को बेहतर और प्रदूषण-मुक्त ट्रांसपोर्ट मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन नई बसों को हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर खास तौर पर डिजाइन किया गया है। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए खास सुविधाएं दी गई हैं ताकि उनका सफर आरामदायक हो सके। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन बसों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।

देशभर में महाशिवरात्रि पर्व की धूम, भगवान महाकाल के लिए बना 11 फुट का सेहरा

-12 ज्योतिर्लिंग और शिव मंदिरों में देर रात से ही दर्शन-पूजन करने भक्त पहुंचे

नई दिल्ली,(ईएमएस)। देशभर में महाशिवरात्रि पर्व की धूम है। 12 ज्योतिर्लिंग और शिव मंदिरों में आधी रात से ही दर्शन-पूजन करने भक्त पहुंच गए। मध्यप्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के पट रात 2.30 बजे से खुले हैं। यहां लगातार 44 घंटे दर्शन-पूजन किया जाएगा। इस दौरान शयन आरती नहीं होगी। सोमवार दोपहर 12 बजे साल में एक बार होने वाली भस्म आरती भी होगी। महाकाल का दूल्हे के रूप में श्रृंगार करने के लिए 3 क्विंटल फूल मंगाए गए हैं। 100 किलो आंकड़े के फूल, सवा लाख बेल पत्र, 200 किलो देसी फूल से बना 11 फुट का सेहरा बनाया गया है। मध्यप्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर मंदिर को रात 3 बजे से दर्शन के लिए खोला गया। यहां 24 घंटे लगातार दर्शन पूजन किया जाएगा।

वहीं, काशी के विश्वनाथ मंदिर में रात 2ः15 बजे मंगला आरती की गई। 3ः30 बजे मंदिर दर्शन के लिए खुल गया। यहां रात से भक्तों की लंबी लाइन लगी है। झारखंड के देवघर में बाबाधाम मंदिर में शनिवार को पंचशूलों की विशेष पूजा की गई। इसके बाद मंदिर के शिखरों पर पंचशूलों की पुनर्स्थापना के साथ ही बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती का पारंपरिक गठबंधन भी हुआ। यहां महाशिवरात्रि पर सुबह 3ः15 बजे विशेष पूजा की गई। सुबह 4ः25 बजे मंदिर के पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। रविवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में शिव-पार्वती विवाह होगा। शाम को शिव बारात निकाली जाएगी।

महात्मा मंदिर में अमित शाह का बड़ा ऐलान, अब राशन वितरण होगा पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी

*** राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए किसानों और गरीबों के हित में केंद्र सरकार की योजनाओं का किया उल्लेख**

*** गुजरात से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव, सीबीडीसी और 'अनाज एटीएम' का शुभारंभ**

गांधीनगर । यहां के महात्मा मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले कई प्रकल्पों का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी' (सीबीडीसी) आधारित आधुनिक वितरण प्रणाली और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 'अनाज एटीएम' की शुरुआत की गई। इस नई व्यवस्था के तहत राशन के पूरे स्टॉक की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी, यहां तक कि विदेश से भी इसकी निगरानी की जा सकेगी। सरकार का दावा है कि इससे वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और भ्रष्टाचारमुक्त बनेगी।

अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि पहले दिल्ली से भेजे गए 5 किलो अनाज में से बीच रास्ते में चोरी हो जाती थी, लेकिन अब तकनीक और डिजिटल राशन कार्ड के जरिए एक दाना भी गायब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गुजरात में तैयार इस नई मशीन के जरिए गरीबों की सुरक्षा की नई शुरुआत की गई है। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता किसी भी मंच पर उनसे बहस करने को तैयार हैं। शाह ने कहा कि देश की जनता ने 2014 में ही कांग्रेस को 'टाटा-बाय बाय' कह दिया था। कांग्रेस ने केवल 'गरीबी हटाओ' के नारे दिए, जबकि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 60 करोड़ गरीबों का जीवन स्तर सुधारा और 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला।

किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए शाह ने कहा कि अमेरिका के साथ संभावित ट्रेड डील से भारतीय किसान सुरक्षित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की सुरक्षा के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के समय कृषि बजट 26 हजार करोड़ रुपये था, जिसे भाजपा सरकार ने बढ़ाकर 1 लाख 26 हजार करोड़ रुपये कर दिया। साथ ही किसानों के खातों में सीधे 6 हजार रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें कर्ज लेने की जरूरत कम हुई है। डेयरी और मत्स्य उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

तारिक रहमान के शपथग्रहण में पीएम मोदी नहीं, ओम बिरला होंगे शामिल

-ढाका में होने वाले समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे लोकसभा अध्यक्ष

नई दिल्ली।

बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने 12 फरवरी 2026 को आयोजित चुनाव में 300 में से 212 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।

भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होंगे। भारत की ओर से इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रतिनिधित्व करेंगे। यह समारोह 17 फरवरी को ढाका में आयोजित होगा।

भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनी गई नई सरकार का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को फोन कर जीत की बधाई भी दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ओम बिरला की भागीदारी दोनों देशों के बीच निरंतर सहयोग और संवाद का संकेत है। इसे भारत की ओर से पड़ोसी देशों के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों और पारस्परिक सम्मान पर आधारित संबंधों को प्राथमिकता देने के रूप में देखा जा रहा है। नई सरकार से क्षेत्रीय स्थिरता और विकास में सकारात्मक भूमिका निभाने की उम्मीद जताई जा रही है।

बांग्लादेशः साउथ प्लाजा में शपथ लेंगे तारिक रहमान, भारत समेत 13 देशों को आमंत्रण

ढाका ।

बांग्लादेश के आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की ऐतिहासिक जीत के बाद अब देश की बागडोर संभालने की औपचारिकताएं तेज हो गई हैं। आगामी 17 फरवरी को नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री और उनके पूरे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने जा रहा है। इस भव्य समारोह के लिए बांग्लादेश ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट और वैश्विक कूटनीति को मजबूती देते हुए भारत और पाकिस्तान समेत कुल 13 देशों को निमंत्रण भेजा है। आमंत्रित देशों की सूची में चीन, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्र शामिल हैं। इस बार का यह समारोह कई मायनों में अनूठा और ऐतिहासिक होने वाला है। परंपरा से हटकर, यह शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन के बजाय राष्ट्रीय संसद परिसर के साउथ प्लाजा में आयोजित किया जा रहा है। यह बदलाव नए राजनीतिक युग की शुरुआत के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। संवैधानिक रूप से यह शपथ ग्रहण प्रक्रिया कुछ

चुनौतियों और विशेष बदलावों के बीच संपन्न होगी। सामान्यतः सांसदों को पद की शपथ निवर्तमान अध्यक्ष (स्पीकर) द्वारा दिलाई जाती है, लेकिन वर्तमान में पूर्व अध्यक्ष शिरीन शरमिन चौधरी के इस्तीफे और उपाध्यक्ष के जेल में होने के कारण एक कानूनी संकट पैदा हो गया था। इस संवैधानिक बाधा को दूर करने के लिए राष्ट्रपति ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन को नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने के लिए अधिकृत किया है।

ममता बनर्जी ने तारिक भाई को भेजा फूल और मिठाइयां, रमजान की अग्रिम मुबारकबाद

-रहमान 17 फरवरी को लेंगे शपथ

कोलकाता।

बांग्लादेश की राजनीति में बड़े बदलाव के तौर पर तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने 13वें संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पार्टी को दो-तिहाई बहुमत मिलने के बाद तारिक रहमान 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह के लिए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाई रहमान को वधाई देने के साथ ही फूलों का गुलदस्ता और मिठाइयां भेजकर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

तारिक रहमान को मिली शानदार जीत के बाद पड़ोसी भारत समेत अनेक देशों ने उन्हें बधाई प्रेषित की है। यहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तारिक रहमान को फूलों का गुलदस्ता और मिठाइयाँ भेजकर अपनी शुभकामनाएँ दी हैं। बीएनपी चेयरमैन के राजनीतिक कार्यालय की ओर से जारी बयान में

बताया गया, कि शनिवार को गुलशन स्थित कार्यालय में बीएनपी मीडिया सेल सदस्य अतिउर रहमान रुमन ने सीएम ममता बनर्जी की ओर से भेजे गए उपहार को प्राप्त किया।

इससे एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर तारिक रहमान को 'तारिक भाई' संबोधित करते हुए चुनावी जीत की बधाई दी थी। उन्होंने अपने संदेश में बांग्लादेश की जनता को शुभकामनाएँ देते हुए अग्रिम रमजान की मुबारकबाद भी दी। ममता बनर्जी ने लिखा कि यह जीत लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है और इससे क्षेत्रीय सहयोग को नई दिशा मिलेगी।

एआई इम्पैक्ट समिट दिल्ली में कल से, 20 देशों के नेता व टेक लीडर्स होंगे शामिल

-इस ग्लोबल मीटिंग में एआई टेक्नोलॉजी की ग्रोथ से जुड़े रिस्क पर होगा फोकस

नई दिल्ली। दिल्ली में होने जा रहे एआई इम्पैक्ट समिट में करीब 20 देशों के नेता और यूनाइटेड नेशंस चीफ के भाग लेने की उम्मीद है। कई टेक लीडर्स भी इस समिट में शामिल होने वाले हैं। यह समिट सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार यानी 20 फरवरी तक चलेगी। यह पांच दिनों का इवेंट है, जो नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। इसे अब तक का सबसे बड़ा एडिशन बताया जा रहा है, यह चौथी सालाना ग्लोबल मीटिंग होगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की तेजी से ग्रोथ से जुड़े रिस्क और अवसरों पर फोकस करेगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि यह समिट एआई के लिए आगे के रास्ते पर बातचीत करने के लिए दुनिया भर के ग्लोबल लीडर्स, पॉलिसीमेकर्स, इनोवेटर्स और एक्सपर्ट्स को एक साथ लाएगी।

एआई इम्पैक्ट समिट में दुनियाभर के नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जिनमें शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी- यूएई, शेरिंग तोबगे, पीएम-भूटान, एडमंड लारा मोंटानो, वाइस प्रेसिडेंट-बोलीविया, लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा, प्रेसिडेंट-ब्राजील, आंद्रेज प्लेनकोविक, पीएम-क्रोएशिया, अलार करिस, राष्ट्रपति-एस्टोनिया, पेटेरी ओर्पो, पीएम-फिनलैंड, इमैनुएल मैक्रों, राष्ट्रपति-फ्रांस, किरियाकोस मित्सोटाकिस, पीएम-ग्रीस, डॉ. भारत जगदेव, वाइस प्रेसिडेंट-गुयाना, ओल्जास बेक्टेनोव, पीएम-कजाकिस्तान, एलोइस, लिकटेंस्टीन की रियासत के वंशानुगत राजकुमार-लिकटेंस्टीन, डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम, पीएम-मॉरिशस, अलेक्जेंडर वुसिक, राष्ट्रपति-सर्बिया, पीटर पेलेग्रिनी, राष्ट्रपति-स्लोवाकिया, पेड्रो सांचेज पेरेज-कास्टेजोन, राष्ट्रपति-स्पेन, अनुरा कुमारा डिसानायका, प्रेसिडेंट-श्रीलंका, सेबेस्टियन पिल्ले, वाइस प्रेसिडेंट-सेशेल्स, गाय परमेलिन, प्रेसिडेंट-स्विट्जरलैंड, डिक शूफ, पीएम-नीदरलैंड्स शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ यूएन के दूसरे सीनियर अधिकारियों के भी नई दिल्ली में होने वाले इस अहम समिट में मौजूद रहने की उम्मीद है।

यूएन चीफ के साथ यूएन ह्यूमन राइट्स के हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क, डिजिटल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंडर-सेक्रेटरी-जनरल और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अमनदीप सिंह गिल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन के डायरेक्टर-जनरल गिल्बर्ट एफ हौंगबो, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की सेक्रेटरी-जनरल डोरेन बोगदान-मार्टिन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए सेक्रेटरी-जनरल के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव कमल किशोर भी होंगे।

गूगल के सुंदर पिचाई और ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन समेत कई टेक लीडर्स के इस समिट में शामिल होने की उम्मीद है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

रेलवे सुधारों पटरी पर नई एक्सप्रेस

(लेखक-/ विनोद कुमार सिंह)

ऑन-बोर्ड सेवाओं से लेकर गतिशक्ति कार्गो टर्मिनलों तक भारत के परिवहन परिदृश्य में ऐतिहासिक परिवर्तन - अर्थात सुधारों की पटरी भारतीय रेल नई रफ्तार लगाने के लिए तत्पर है*

भारतीय रेल केवल एक परिवहन प्रणाली नहीं है,बल्कि यह भारत की आर्थिक,सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की धमनियों में प्रवाहित होने वाला जीवन प्रवाह है। ब्रिटिश काल में बिछी रेल पटरियों से लेकर स्वतंत्र भारत के औद्योगिक और सामाजिक पुनर्निर्माण तक,रेल ने देश को जोड़ा,गति दी और एक राष्ट्र की भौगोलिक विविधताओं को एक साझा अनुभव में पिरोया।आज जब भारत 'विकसित भारत' के संकल्प के साथ 21वीं सदी के तीसरे दशक में आगे बढ़ रहा है,तब भारतीय रेल स्वयं को एक पारंपरिक परिवहन सेवा से बदलकर एक आधुनिक, तकनीक-संचालित,लॉजिस्टिक्स- सक्षम और ग्राहक-केंद्रित परिवहन इकोसिस्टम के रूप में पुनर्परिभाषित कर रही है।

रेल मंत्रालय द्वारा घोषित 'बेहतर ऑन-बोर्ड सेवाएं' और 'गतिशक्ति कार्गो टर्मिनलों के माध्यम से रेल-आधारित लॉजिस्टिक्स' की रणनीति,भारतीय रेल के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखी जा सकती है। यह सुधार केवल यात्रियों की सुविधा तक सीमित नहीं है,बल्कि यह भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर,औद्योगिक उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला,और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाला कदम है।रेल

> भारतीय रेल के सुधारों की यह नई एक्सप्रेस केवल पटरियों पर दौड़ती ट्रेन नहीं,बल्कि भारत के विकास पथ पर दौड़ती परिवर्तन की रेलगाड़ी है। यह सुधार भारत के आम नागरिक को बेहतर यात्रा अनुभव, उद्योग को कुशल लॉजिस्टिक्स,और राष्ट्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदान करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

यात्रा अनुभव के संदर्भ में भारतीय रेल लंबे समय से आम नागरिकों की जीवनरेखा रही है,परंतु यात्रियों की अपेक्षाएं समय के साथ बदलती गई हैं।स्वच्छता,आराम,समय बद्धता और सेवा गुणवत्ता अब केवल सुविधा नहीं बल्कि अधिकार के रूप में देखी जाने लगी हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में रेलवे द्वारा सामान्य डिब्बों सहित सभी कोचों में निरंतर सफाई की व्यवस्था लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक महत्व रखता है। सामान्य श्रेणी के यात्रियों को अब तक सुविधाओं के मामले में अक्सर उपेक्षित माना जाता रहा है,किंतु वर्तमान सुधारों का केंद्रबिंदु यही वर्ग है,जो भारतीय रेल के सामाजिक लोकतंत्र का प्रतीक है। रेलवे द्वारा बेहतर लिनन प्रबंधन और कोच सफाई के लिए सेवा प्रदाता की पहचान तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव,भारतीय रेल के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम है।एआई सक्षम निगरानी प्रणाली केवल सफाई की निगरानी तक सीमित नहीं रहेगी,बल्कि यह सेवा गुणवत्ता,शिकायत निवारण और प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक डेटा-आधारित प्रणाली के रूप में विकसित हो सकती है।इससे रेलवे प्रशासन के निर्णय अधिक वैज्ञानिक,पारदर्शी और उत्तरदायी बनेंगे।रेलवे सुधारों का दूसरा और अधिक व्यापक आयाम रेल- आधारित लॉजिस्टिक्स और मल्टी-मॉडल टर्मिनलों के रूप में सामने आया है।वर्तमान में देश में 124 मल्टी- मॉडल टर्मिनल कार्यरत हैं,जिन्हें अब 'कार्गो-प्लस- प्रोसेसिंग हब' के रूप में विकसित करने की योजना है।इसका अर्थ यह है कि रेल टर्मिनल केवल माल लोड और अनलोड करने का स्थान नहीं रहेंगे,बल्कि वे मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग,भंडारण,प्रसंस्करण और वितरण के केंद्र बनेंगे।यह अवधारणा विकसित देशों के लॉजिस्टिक्स मॉडल के अनुरूप है, जहां परिवहन केंद्र आर्थिक गतिविधियों के क्लस्टर के रूप में कार्य करते हैं।इसके अतिरिक्त, 500 से अधिक गतिशक्ति कार्गो टर्मिनलों की योजना भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत विभिन्न परिवहन माध्यमों—रेल, सड़क, जलमार्ग और वायु मार्ग—के एकीकरण का जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है,भारतीय रेल उसमें केंद्रीय भूमिका निभाने जा रही है। रेल-आधारित लॉजिस्टिक्स लागत-कुशल,ऊर्जा-कुशल और पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ है। भारत जैसे विशाल और विविध भौगोलिक संरचना वाले देश में, जहां माल परिवहन की लागत सकल घरेलू उत्पाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है,रेल आधारित लॉजिस्टिक्स सुधार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं।

लॉजिस्टिक्स सुधारों का प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि,उद्योग,व्यापार और निर्यात क्षेत्र पर पड़ेगा।कृषि उत्पादों की समयबद्ध ढुलाई,औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति, तैयार माल का वितरण और ई-कॉमर्स की बढ़ती मांग ऑल इन क्षेत्रों में रेल आधारित कार्गो नेटवर्क एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।विशेष रूप से भारत के अंतर्देशीय और दूरस्थ क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों का विस्तार होगा,जहां सड़क और अन्य परिवहन साधन सीमित हैं।

भारतीय रेल द्वारा फील्ड लर्निंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के आधार पर इन सुधारों को पूरे नेटवर्क में लागू करने की योजना, प्रशासनिक परिपक्वता और व्यावहारिक दृष्टिकोण का संकेत है। अक्सर बड़े पैमाने पर लागू की गई योजनाएं जमीनी स्तर पर असफल हो जाती हैं,किंतु चरणबद्ध कार्यान्वयन और फील्ड अनुभव से सीखने की रणनीति नीति निर्माण में आधुनिक शासन मॉडल को दर्शाती है।रेलवे सुधारों का यह अभियान केवल तकनीकी या प्रशासनिक सुधार नहीं है,बल्कि यह एक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का वाहक है।भारतीय रेल लोकतांत्रिक भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक संस्थान है,जहां अमीर और गरीब, शहरी और ग्रामीण,सभी एक ही डिब्बे में यात्रा करते हैं।इसलिए जब सामान्य कोचों की सफाई और सेवा गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाती है,तो यह सामाजिक न्याय और समावेशन की भावना को भी प्रतिबिंबित करता है।डिजिटल निगरानी,एआई आधारित प्रणाली और सेवा प्रदाताओं के माध्यम से सफाई और लिनन प्रबंधन की गुणवत्ता सुधारने का उद्देश्य केवल दृश्य स्वच्छता नहीं,बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और यात्री संतोष को बढ़ाना भी है। स्वच्छता केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि गरिमा और सुरक्षा का प्रश्न है।कोविड-19 महामारी के बाद स्वच्छता और स्वास्थ सुरक्षा के प्रति नागरिकों की संवेदनशीलता बढ़ी है , भारतीय रेल का यह कदम उसी चेतना का परिणाम है।भारतीय रेल द्वारा लॉजिस्टिक्स हब के रूप में टर्मिनलों के विकास से निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे।सार्वजनिक- निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से आधुनिक वेयरहाउसिंग,कोल्ड स्टोरेज,प्रोसेसिंग यूनिट्स और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किए जा सकते हैं।इससे रोजगार सृजन,क्षेत्रीय विकास और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।भारत की अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स की लागत लगभग 13-14 प्रतिशत आंकी जाती है, जो विकसित देशों की तुलना में अधिक है।रेल आधारित लॉजिस्टिक्स सुधारों से इस लागत में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। यदि यह लक्ष्य सफल होता है,तो भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे,निर्यात बढ़ेगा और 'मेक इन इंडिया' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानों को ठोस आधार मिलेगा।रेलवे सुधारों का यह अभियान उस व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है,जिसमें भारत अपने बुनियादी ढांचे को आधुनिक,टिकाऊ और डिजिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाई-स्पीड रेल,समर्पित माल गलियारे, स्टेशन पुनर्विकास, .वंदे भारत ट्रेनें,और डिजिटल टिकटिंग -ये सभी पहलें एक समग्र परिवहन क्रांति की ओर संकेत करती हैं।ऑन-बोर्ड सेवाओं में सुधार और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का विस्तार इस क्रांति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।इस परिवर्तन की सफलता प्रशासनिक क्षमता,तकनीकी कार्यान्वयन, वित्तीय संसाधनों और नागरिक सहभागिता पर निर्भर करेगी।सेवा प्रदाताओं की पारदर्शी नियुक्ति, एआई सिस्टम की विश्वसनीयता, डेटा सुरक्षा,और जमीनी स्तर पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण - ये सभी कारक सुधारों की स्थिरता और प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे।

भारतीय रेल के सुधारों की यह नई एक्सप्रेस केवल पटरियों पर दौड़ती ट्रेन नहीं,बल्कि भारत के विकास पथ पर दौड़ती परिवर्तन की रेलगाड़ी है। यह सुधार भारत के आम नागरिक को बेहतर यात्रा अनुभव, उद्योग को कुशल लॉजिस्टिक्स,और राष्ट्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदान करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

जब सामान्य कोच का यात्री स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में यात्रा करेगा,जब किसान का उत्पाद समय पर बाजार पहुंचेगा,जब उद्योग को कच्चा माल सस्ती और तेज़ गति से मिलेगा,और जब भारत का निर्यात वैश्विक बाजार में नई पहचान बनाएगा - तब यह कहा जा सकेगा कि भारतीय रेल ने केवल पटरियां नहीं बिछाईं,बल्कि विकसित भारत की राह भी प्रशस्त की।भारतीय रेल के इस परिवर्तन कारी अभियान को केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं,बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जाना चाहिए।यह मिशन भारत की गति, दिशा और नियति को आकार देने वाला है।रेल की सीटी केवल स्टेशन पर आगमन का संकेत नहीं,बल्कि भारत के भविष्य के आगमन की उद्घोषणा है। वही ऑन-बोर्ड सेवाओं से लेकर गतिशक्ति कार्गो टर्मिनलों तक भारत के परिवहन परिदृश्य में ऐतिहासिक परिवर्तन - अर्थात सुधारों की पटरी भारतीय रेल नई रफ्तार लगाने के लिए तत्पर है ।

संपादकीय

शहरी विकास का एजेंडा

केंद्रीय कैबिनेट ने शहरी चुनौती कोष को मंजूरी दी है, जिसके तहत अगले पांच वर्षों में शहरों के उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मिलेगी। यह योजना स्मार्ट सिटी योजना की सीख पर आधारित है, जिसमें केंद्र 25ब्न लागत वहन करेगा यदि 50ब्न बाजार से जुटाया जाए। इसका उद्देश्य शहरों को आर्थिक विकास के केंद्र बनाना और नागरिक सुविधाओं में सुधार करना है, जिससे कुल चार लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट शुरू होने की उम्मीद है। केंद्रीय कैबिनेट ने शहरों में उच्च गुणवत्ता वाले आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए अर्बन चैलेंज फंड (शहरी चुनौती कोष) को जो स्वीकृति दी, उसके तहत अगले पांच वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। नि:संदेह शहरों के कायाकल्प की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है और आशा की जाती है कि इस योजना का हश्र स्मार्ट सिटी योजना की तरह नहीं होगा। कैबिनेट के फैसले से यह लगता भी है कि स्मार्ट सिटी योजना के अपेक्षित परिणाम न मिलने से सीख ली गई है और इसीलिए यह प्रविधान किया गया है कि केंद्र सरकार शहरों की दशा सुधारने वाली परियोजना की लागत का 25 प्रतिशत हिस्सा तभी वहन करेगी, जब उसके लिए कम से कम 50 प्रतिशत धन बाजार से जुटाया जाए। शेष 25 प्रतिशत राशि का प्रबंध राज्य सरकारों या फिर संबंधित शहरों के स्थानीय निकायों को करना होगा। राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे शहरों के स्थानीय निकायों के साथ मिलकर ऐसा करने में समर्थ हों। चूंकि यह योजना इस वर्ष के बजट के उस प्रविधान के अनुरूप है, जिसके तहत शहरों को वृद्धि के केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि मोदी सरकार शहरों की दशा सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि शहरी चुनौती कोष से अगले पांच वर्षों में शहरों में चार लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। यदि ऐसा हो सके तो इससे बेहतर और कुछ नहीं, क्योंकि हमारे शहर नागरिक सुविधाओं के अभाव से जूझने के साथ जर्जर बुनियादी ढांचे का सामना कर रहे हैं। वे अनियोजित विकास का पर्याय भी बन रहे हैं। इसी कारण शहरों के बुनियादी ढांचे को संवारने अथवा नागरिक सुविधाओं को ठीक करने वाली कोई भी परियोजना कुछ ही वर्षों में अपर्याप्त अथवा समस्याग्रस्त नजर आने लगती है। इस विषम स्थिति से तभी बचा जा सकता है, जब शहरों के आधारभूत ढांचे का विकास दीर्घकालिक चुनौतियों, पर्यावरण हितों और आबादी के लगातार बढ़ते दबाव को ध्यान में रखकर किया जाए। जब ऐसा होगा, तभी हमारे शहर नगरीय जीवन को सुविधाजनक बनाने के साथ आर्थिक विकास के केंद्र बन पाएंगे। यदि भारत को सचमुच विकसित देश बनना है तो उसे अपने छोटे-बड़े शहरों को संवारना ही होगा, क्योंकि एक तो आने वाले समय में शहरों में रहने वाली आबादी तेजी से बढ़ेगी और दूसरे यह किसी से छिपा नहीं कि आज के युग में शहर आर्थिक प्रगति के इंजन हैं। यह अच्छा है कि केंद्र सरकार दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के साथ एक लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले औद्योगिक शहरों को भी अपनी नई योजना के दायरे में लाना चाहती है, लेकिन बात तब बनेगी जब राज्य भी अपने शहरों की सूरत संवारने की ललक दिखाएंगे।

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की वैचारिक क्रांति

(लेखक- ललित गर्ग)

बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर इतिहास के मोड़ पर खड़ी है। लगभग दो दशकों के लंबे अंतराल के बाद यदि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौटती है और तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तक पहुंचते हैं, तो यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि राजनीतिक दिशा परिवर्तन का संकेत होगा। 299 सीटों में से 212 पर विजय का दावा इस बात का प्रमाण है कि मतदाता लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता, अंतरिम व्यवस्थाओं और वैचारिक ध्रुवीकरण से बाहर निकलकर एक निर्णायक जनादेश देना चाहता है। छात्र आंदोलन से उपजी नेशनल सिटीजन पार्टी का मात्र छह सीटों पर सिमटना भी इस तथ्य को पुष्ट करता है कि जनभावना प्रयोगधर्मिता से आगे बढ़कर स्थायित्व की ओर झुक रही है। लगभग अठारह महीने से चल रही अंतरिम व्यवस्था के अवसान के साथ बांग्लादेश एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहा है, पर प्रश्न यह है कि यह अध्याय उदार लोकतंत्र का होगा या किसी नए प्रकार के वैचारिक वर्चस्व का?

बांग्लादेश का इतिहास संघर्ष, त्याग और पहचान की जिजीविषा से निर्मित हुआ है। 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की निर्णायक भूमिका केवल सैन्य सहायता तक सीमित नहीं थी, वह सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग का भी प्रतीक थी। परंतु पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक ध्रुवीकरण, कट्टरवादी विमर्श और बाहरी प्रभावों ने उस ऐतिहासिक आत्मीयता पर धुंध डालने का प्रयास किया। अंतरिम सरकार के दौरान जिस प्रकार वैचारिक कठोरता और प्रशासनिक असमंजस दिखा, उसने अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने दोनों को प्रभावित किया। ऐसे समय में स्पष्ट जनादेश को स्थिरता का अवसर माना जा सकता है, बशर्ते सत्ता इसे प्रतिशोध का माध्यम न बनाए, बल्कि पुनर्निर्माण का औजार बनाए।

तारिक रहमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती सांप्रदायिक सौहार्द की पुनर्स्थापना होगी। बांग्लादेश का सामाजिक ढांचा बहुलतावादी है, वहां अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और सम्मान केवल नैतिक दायित्व नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विश्वसनीयता की कसौटी है। यदि नई सरकार कट्टरवाद से दूरी बनाकर विकासोन्मुखी एजेंडा अपनाती है, तो वह न केवल आंतरिक स्थिरता ला सकती है, बल्कि दक्षिण एशिया में एक सकारात्मक उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकती है। पर यदि चुनावी विजय को वैचारिक वर्चस्व के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो यह जनादेश अवसर से अधिक संकट में बदल सकता है।

आर्थिक मोर्चे पर बांग्लादेश ने पिछले दशक में उल्लेखनीय प्रगति की थी। वस्त्र उद्योग, निर्यात वृद्धि और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में उसने मिसाल कायम की। किंतु राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत अनिश्चितता ने निवेशकों के विश्वास को झटका दिया। अब नई सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह आर्थिक सुधारों को गति दे, रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करे और विदेशी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाए। विकास की फ्रनई गंगाफ्र तभी बहेगी जब शासन पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी होगा। केवल नारे या राष्ट्रवाद की तीखी ध्वनियां आर्थिक संकट का समाधान नहीं बन सकतीं।

भारत-बांग्लादेश संबंध इस चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक हैं। दोनों देशों के बीच साझा इतिहास, सांस्कृतिक निकटता और आर्थिक परस्परता है। सीमा प्रबंधन, जल बंटवारा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दे परस्पर विश्वास से ही सुलझ सकते हैं। हाल के वर्षों में पाकिस्तान के साथ बढ़ती निकटता और भारत के प्रति संदेहपूर्ण बयानबाजी ने संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा किया। यदि नई सरकार क्षेत्रीय संतुलन की नीति अपनाते हुए भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संवाद पुनः स्थापित करती है, तो यह दोनों देशों के हित में होगा। भारत ने बांग्लादेश के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस ऐतिहासिक साझेदारी को भावनात्मक नहीं, व्यावहारिक आधार पर पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

यह भी ध्यान रखना होगा कि दक्षिण एशिया की राजनीति अब केवल द्विपक्षीय समीकरणों तक सीमित नहीं है। चीन की बढ़ती उपस्थिति, अमेरिका की रणनीतिक रुचि और पाकिस्तान की पारंपरिक भूमिका-इन सबके बीच बांग्लादेश को संतुलित कूटनीति अपनानी होगी। यदि नई सरकार वैचारिक आग्रहों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखती है, तो वह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में एक परिपक्व भूमिका निभा सकती है। परंतु यदि विदेश नीति घरेलू राजनीति का विस्तार बन गई, तो अस्थिरता का चक्र फिर दोहराया जा सकता है।

इस चुनाव का एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि बांग्लादेश का मतदाता अब निर्णायकता चाहता है। लंबे समय तक आंदोलन, विरोध और अंतरिम प्रयोगों से थका समाज स्थिर शासन की आकांक्षा रखता है। किंतु स्थिरता केवल बहुमत से नहीं आतीय वह संस्थाओं की मजबूती, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वायत्तता से आती है। नई सरकार को यह समझना होगा कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं, बल्कि असहमति को सम्मान देने की संस्कृति का नाम है। यदि विपक्ष को हाशिये पर धकेला गया या आलोचना को देशविरोध का रूप दिया गया, तो लोकतांत्रिक ऊर्जा क्षीण हो जाएगी।

बांग्लादेश के लिए यह क्षण आत्ममंथन का भी है। क्या वह अपनी पहचान को केवल धार्मिक राष्ट्रवाद तक सीमित करेगा, या भाषा, संस्कृति और बहुलता की उस विरासत को आगे बढ़ाएगा जिसने उसे जन्म दिया? मुक्ति संग्राम की मूल भावना सामाजिक न्याय और समान अवसर की थी। यदि नई सत्ता उस भावना को पुनर्जीवित करती है, तो यह जनादेश ऐतिहासिक सिद्ध होगा। अन्यथा यह अवसर भी इतिहास की एक और चूकी हुई संभावना बन सकता है।

भारत की दृष्टि से भी यह चुनाव महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली को प्रतिक्रिया में उतावलापन नहीं, बल्कि धैर्य और कूटनीतिक परिपक्वता दिखानी होगी। पड़ोसी देश की संप्रभुता और जनादेश का सम्मान करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाना ही दीर्घकालिक हित में है। सीमा पार आतंकवाद, अवैध घुसपैठ और तस्करी जैसे मुद्दों पर सख्ती के साथ-साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संवाद को भी सुदृढ़ करना होगा। संबंधों में भावनात्मकता के बजाय व्यावहारिकता और पारस्परिक सम्मान की नींव आवश्यक है।

अंततः यह चुनाव बांग्लादेश के लिए निर्णायक इसलिए है क्योंकि यह केवल सरकार बदलने का अवसर नहीं, बल्कि शासन की शैली और राष्ट्रीय दिशा तय करने का क्षण है। यदि नई सरकार कट्टरवाद से मुक्त, समावेशी और विकासोन्मुखी नीति अपनाती है, तो वह बांग्लादेश को स्थिरता और समृद्धि के पथ पर अग्रसर कर सकती है।

उत्तम शरण है धर्म

धर्म के बारे में भिन्न-भिन्न अवधारणाएं हैं। कुछ जीवन के लिए धर्म की अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं। कुछ लोगों का अभिमत है कि धर्म ढकोसला है। वह आदमी को पंगु बनाता है और रूढ़ धारणाओं के घेरे में बंदी बना लेता है। शायद इन्हीं अवधारणाओं के आधार पर किसी ने धर्म को अमृत बताया और किसी ने अफीम की गोली। ये दो विरोधी तत्व हैं। इन दोनों ही तथ्यों में सत्यांश हो सकता है, यह अनेकांतवादी चिंतन का फलित है। धर्म की अनिवार्यता स्वीकार करने वालों के लिए धर्म है अंधकार से प्रकाश की यात्रा। आलोक आदमी के भीतर है। उसे पाने के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आलोक तक वही पहुंच सकता है, जो अंतमरुखी होता है। अंतमरुखता धर्म है और बहिर्मुखता अधर्म है। अंतमरुखता प्रकाश है और बहिर्मुखता अंधकार है। अंतर्मुखता धर्म है और बहिर्मुखता अधर्म है। अंतर्मुखता आचार है और बहिमरुखता अतिचार है। जो व्यक्ति जितना भीतर झांकता है, उतना ही धर्म के निकट होता है।

धर्म को मानने वाले वे प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने पूजा और उपासना को ही धर्म मान लिया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि धर्म-स्थानों में जाने वाले व्यक्तियों के हर आचरण को धर्म समझ लिया। धार्मिक क्रियाकांडों तक जिनकी पहुंच सीमित हो गई और धार्मिकों की दोहरी जीवनपद्धति को देखकर जो उलझ गए। भगवान महावीर अपने युग के सफल धर्म-प्रवर्तक थे। धर्म को जानने या पाने के लिए उन्हें किसी परंपरा का अनुगमन नहीं करना पड़ा। उन्होंने उस समय धर्म के द्विविध रुप का निरूपण किया। उनकी दृष्टि में धर्म का एक रूप अमृतोपम था तो दूसरा प्राणलेवा जहर जैसा।

विचार मंथन

अमेरिका- भारत में संविधान और लोकतंत्र के नये मानक?

(लेखक- सनत जैन)

विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश अमेरिका और भारत आज केवल राजनीतिक एवं व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को नये तरीके से परिभाषित करने के केंद्र बन रहे हैं। इस कारण अमेरिका और भारत की संघीय लोकतांत्रिक एवं प्रशासकीय व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल उठने लगे हैं। बदलते वैश्विक परिदृश्य में तकनीकी क्रांति, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक विविधताओं के बीच इन दोनों देशों ने संविधान और लोकतंत्र की नई व्याख्या करने की शुरुआत कर दी है, जो शासक आधारित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं जवाबदेही तय होती है। भारत में पिछले कई वर्षों से सत्ता का केंद्रीकरण होता जा रहा है। अमेरिका में भी दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं, उससे भी शासन व्यवस्था में ट्रम्प का एकाधिकार अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के जो राज्य हैं, उनकी दूरी केंद्रीय सत्ता से बढ़ती चली जा रही है। नई व्याख्या परंपरागत मूल्यों को बनाए रखते हुए समयानुकूल बदलाव के लिए लोकतांत्रिक पद्धति एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण पूर्व की तरह बना रहेगा, तभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत रहेंगी। भारत का संविधान विविधता में एकता का प्रतीक है। भारत में विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति और परंपराओं की असंख्य धाराएँ संविधान एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समाहित हैं। वहीं अमेरिका का संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मानव अधिकारों की रक्षा एवं संघीय व्यवस्था प्रदान करता है। दोनों देशों ने अपने-अपने ऐतिहासिक अनुभवों से लोकतंत्र को मजबूत किया था। अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम और नागरिक अधिकार आंदोलनों से, वहीं भारत ने स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक न्याय के लिए भारतीय संविधान तैयार किया था। भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और न्यायिक तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर कई चुनौतियों का सामना अमेरिका और भारत दोनों को ही करना पड़ रहा है। चाहे वह, सत्ता के केंद्रीयकरण का मामला हो या फेक न्यूज़ का प्रसार हो। वैधानिक संस्थाओं पर सत्ता का बढ़ता दबाव लोकतंत्र और न्याय तंत्र दोनों को ही प्रभावित कर रहा है। मानव अधिकारों को लेकर वह स्वतंत्रता अब नहीं मिलती, जैसे कुछ समय पहले देखने को मिलती थी। ऐसे समय में भारत और अमेरिका में सत्ता पक्ष द्वारा लोकतंत्र को नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है। यह परिभाषा केवल चुनावी प्रक्रिया और सत्ता तक सीमित नहीं है। अमेरिका और भारत में शासन व्यवस्था की पारदर्शिता, जवाबदेही, डिजिटल अधिकारों और नागरिक अधिकारों को लेकर तनाव के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहा जा रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका मे जो निर्णय ले रहे हैं, उनमें वे अमेरिकन कानूनो को नजर अंदाज कर रहे हैं। राज्य और केंद्र के बीच में भी मतभेद बढ़ते चले जा रहे हैं। यही स्थिति भारत में भी देखने को मिल रही है। डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन एक बड़ी चुनौती है। भारत और अमेरिका दोनों ने तकनीकी कंपनियों के नियमन, डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ट्रेड डील के माध्यम से नई पहल की है। इससे स्पष्ट है, वैश्विक व्यापार संधि के बाद जिस तरह के वैश्विक नियम और कानून बनाए गए थे उनसे हटकर अमेरिका अपने व्यापारिक समझौते करना चाहता है। भारत एवं अन्य देशों पर अमेरिका जो दबाव बना रहा है, उसके कारण वैश्विक स्तर पर अभी तक जो डॉलर की स्वीकार्यता थी, वैश्विक व्यापार में अमेरिका और डॉलर का जो वर्चस्व था, अब उसे चुनौती मिलना शुरू हो गई है। जिसके कारण संपूर्ण दुनिया के देशों में लोकतंत्र और तानाशाही व्यवस्था को लेकर चर्चा होने लगी है। लोकतंत्र अब केवल संसद, सरकार, कार्यपालिका और न्यायालय तक सीमित नहीं रहा। संविधान की भावना मानव अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिजिटल तकनीकि के साथ जवाबदेही तय करना समय की मांग बन चुकी है। वर्तमान संदर्भ में सामाजिक न्याय और समान अवसर को लेकर लोकतंत्र की नई परिभाषा में बदलाव की जरूरत है। अमेरिका में नस्लीय समानता और भारत में सामाजिक भाषा एवं धार्मिक समावेश में संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकार में सभी को समान अवसर और गरिमा सुनिश्चित करने कुछ बदलाव जरूरी हैं। पिछले कुछ वर्षों से सत्ता पाने के लिये अमेरिका और भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है। उसके कारण लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपने-अपने ढंग से ढालने के जो प्रयास हो रहे हैं, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं मानव अधिकारों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, वैश्विक शांति, सामाजिक सोहार्द्र, धार्मिक और आर्थिक स्थिरता के प्रयास, लोकतंत्र की वैश्विक जिम्मेदारी का प्रतीक है। अमेरिका के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जिस तरह का विरोध पनप रहा है। उसने कई तरह की चुनौतियां पैदा कर दी हैं।

लेनोवो इंडिया का राजस्व बढ़ा, डिजिटल और एआई खंड में मजबूती

- तीसरी तिमाही में 8,145 करोड़ रुपये का राजस्व मिला

नई दिल्ली । प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लेनोवो इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में अपने राजस्व में 7 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है, जो बढ़कर 8,145 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने इस वृद्धि के लिए भारत में डिजिटलीकरण की गति और एआई (कृत्रिम मेधा) अपनाने को मुख्य कारण बताया है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह प्रदर्शन केवल एक बार का उछाल नहीं है, बल्कि निरंतर बनी रहने वाली मांग को दर्शाता है। मोबाइल, कंप्यूटर/लैपटॉप, टैबलेट और अवसंरचना खंडों में लेनोवो के विस्तृत पोर्टफोलियो ने इस वृद्धि को बल दिया। आईडीसी के आंकड़ों के अनुसार मोटोरोला ने इस तिमाही में भारत में 8.3 फीसदी बाजार हिस्सेदारी हासिल की। इसके अलावा लेनोवो के कंप्यूटर/लैपटॉप व्यवसाय और सर्वर एवं अवसंरचना खंड ने भी सालाना दहाई अंकों में वृद्धि दर्ज की। अे धिकारी ने बताया कि भारत की वैश्विक राजस्व में हिस्सेदारी लगभग 4 फीसदी, जबकि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में यह 24 फीसदी है। भारत केवल राजस्व केंद्र नहीं, बल्कि विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास और एआई प्रतिभा विकास का भी मुख्य केंद्र बन रहा है। सरकार की पीएलआई (उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन) योजना जैसी पहलें इस तंत्र को और मजबूत कर रही हैं। कंपनी का मानना है कि डिजिटलीकरण और एआई अपनाने की गति आने वाले वर्षों में व्यवसायिक विकास को और तेज करेगी।

बेजेल इंटरनेशनल दे रही है पहली बार बोनस शेयर

मुंबई । बेजेल इंटरनेशनल` लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह अपने निवेशकों को पहली बार बोनस शेयर देगी। कंपनी ने तय किया है कि हर शेयरधारी को 1ङ्1 रेशियो में बोनस शेयर मिलेगा। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 18 फरवरी 2026 रखी गई है। यानी इस दिन जिन निवेशकों के नाम कंपनी की रिकॉर्ड बुक में होंगे, उन्हें ही बोनस शेयर का लाभ मिलेगा। पिछले दो हफ्तों में बेजेल इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयरों में 17.59 फीसदी की तेजी आई है। हालांकि, एक साल में निवेशकों को 21 फीसदी का नुकसान हुआ है। कंपनी का 52-सप्ताह का हाई 94.55 और लो 50.05 रुपए है। बेजेल ने लंबी अवधि में शानदार प्रदर्शन दिखाया है। दो साल में 88 फीसदी, तीन साल में 79 फीसदी और पांच साल में 492 फीसदी का रिटर्न निवेशकों को मिला है। कंपनी का मार्केट कैप 18.35 करोड़ रुपए है। दिसंबर 2025 तक प्रमोटर्स के पास 0.08 फीसदी हिस्सेदारी थी, जबकि पब्लिक के पास 94.26 फीसदी शेयर थे।

इंफोसिस ने दिसंबर तिमाही में औसतन 85 फीसदी बोनस का ऐलान किया

नई दिल्ली । देश की प्रमुख आईटी कंपनी इंफोसिस ने दिसंबर तिमाही के लिए कर्मचारियों को औसतन 85 प्रतिशत प्रदर्शन बोनस देने की घोषणा की है। व्यक्तिगत स्तर पर बोनस 75 से 100 फीसदी तक दिया गया। कुछ कर्मचारियों को पिछले क्वार्टर से करीब 15 फीसदी अधिक राशि मिली है। यह वित्त वर्ष 2025-26 का अब तक का सबसे अधिक बोनस माना जा रहा है। जनवरी में जारी तीसरी तिमाही के नतीजों के अनुसार, स्थिर मांग और बड़े डील्स ने कारोबार को मजबूती दी। इसी सकारात्मक प्रदर्शन के चलते इस बार वेरिएबल पे पहले की तुलना में बेहतर है। इंफोसिस में करीब 3.23 लाख कर्मचारी हैं। कंपनी ने नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक वार्षिक मूल्यांकन पूरा किया और दिसंबर में व्यक्तिगत रेटिंग जारी की। आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से विकास के बीच यह बेहतर बोनस कर्मचारियों के मनोबल और विश्वास को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। कर्मचारी अब सालाना वेतन वृद्धि की घोषणा पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, पिछले साल अधिकतर कर्मचारियों को 5-8 फीसदी वृद्धि मिली थी।

वैश्विक कारकों से मिलेगी शेयर बाजार को दिशा

- सोने और चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव भी बाजार की धारणा कर सकता है प्रभावित

मुंबई (ईएमएस)। भारतीय शेयर बाजार ने पिछले सप्ताह आईटी कंपनियों में दबाव के कारण गिरावट का सामना किया। सप्ताह की शुरुआत में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन शुक्रवार को बाजार में भारी गिरावट ने निवेशकों के पोर्टफोलियो पर लाल निशान छोड़ दिए। विशेषज्ञों के अनुसार यह सप्ताह किसी रोलर-कोस्टर राइड से कम नहीं था। निवेशक अब आने वाले सप्ताह की ओर अपनी नजरें लगाए हुए हैं, क्योंकि बाजार में स्थिरता की उम्मीद फिलहाल नहीं है। इस सप्ताह में निवेशक मुख्य रूप से वैश्विक संकेतों पर ध्यान देंगे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मिनट्स जारी होने वाले हैं, जो ब्याज दरों और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति का स्पष्ट संकेत देंगे। इसके अलावा सोने और चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव भी भारतीय बाजार की धारणा को प्रभावित कर सकता है। निवेशक इन संकेतों के आधार पर अपने निवेश निर्णयों को संशोधित कर सकते हैं। घरेलू स्तर पर इस सप्ताह आयात-निर्यात के आंकड़े जारी होंगे। ये आंकड़े बाजार की धारणा को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशक इन आंकड़ों और वैश्विक संकेतों का विश्लेषण करके अपनी रणनीति तय करेंगे। इसके अलावा बैंकिंग, मेटल और आईटी सेक्टर पर भी इन आंकड़ों का असर देखा जा सकता है।

यूनिलीवर का भारत में कारोबार मजबूत, होम केयर खंड में बिक्री बढ़ी

नई दिल्ली ।

ब्रिटेन की बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता सामान कंपनी यूनिलीवर ने कहा है कि अमेरिका के बाद उसका दूसरा सबसे बड़ा बाजार भारत में कारोबार की बुनियादी स्थिति में सुधार हो रहा है। कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजों में यह बात सामने आई। यूनिलीवर ने बताया कि होम केयर खंड में 4.7 प्रतिशत की अंतर्निहित बिक्री वृद्धि और 4 प्रतिशत की बिक्री मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी के अनुसार, यह वृद्धि भारत में उत्पादों की लगातार मजबूत खपत के कारण संभव हुई। कंपनी के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने कहा कि होम केयर खंड में फैब्रिक वॉश और घरेलू देखभाल उत्पादों के अच्छे प्रदर्शन के दम पर भारत में बिक्री की मात्रा मध्यम एकल अंक में बढ़ी। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी ने अब तक की सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी हासिल की। फर्नांडीस ने कहा कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका और भारत यूनिलीवर के लिए स्पष्ट रूप से एंकर मार्केट (मुख्य आधार बाजार) हैं। यूनिलीवर के लिए भारत न केवल बिक्री में वृद्धि का स्रोत बन रहा है, बल्कि कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में भी मदद कर रहा है।

सोना-चांदी में नई तेजी की तैयारी, निवेशकों की नजर रैली पर

एमसीएक्स पर चांदी 3.6 फीसदी बढ़ी, सोना 1,56,200 रुपए पर स्थिर

नई दिल्ली । सोने और चांदी की कीमतों में हालिया उतार-चढ़ाव के बीच बाजार में फिर से तेजी की चर्चा तेज हो गई है। शुक्रवार को एमसीएक्स पर चांदी 8,564 रुपए बढ़कर 2,44,999 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जबकि सोना 305 रुपए की हल्की बढ़त के साथ 1,56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी गिरावट के बाद रिकवरी देखने को मिली। हाजिर चांदी 2.1 फीसदी बढ़कर 77.27 डॉलर प्रति औंस और हाजिर सोना 2.33 फीसदी चढ़कर 5,063 डॉलर प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि सोने के लिए 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। यदि कीमतें 1,60,000 रुपए के ऊपर टिकती हैं, तो 1,65,000-1,70,000 रुपए की ओर नया बुलिश मोमेंटम बन सकता है। चांदी के लिए 2,33,000-2,35,000 रुपए प्रति किलोग्राम का सपोर्ट जोन मजबूत माना जा रहा है। 2,65,000 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट होने पर मीडियम टर्म में 2,80,000 रुपए तक तेजी की संभावना जताई जा रही है। बाजार में रिकवरी को निवेशकों की नई खरीदारी और कमजोर डॉलर संकेतों से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा वैश्विक संकेत, ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी आने वाले दिनों में सोना-चांदी की चाल तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सपोर्ट मजबूत बने हुए हैं और यदि प्रमुख रेजिस्टेंस स्तर टूटते हैं तो बुलियन मार्केट में फिर से बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। निवेशक अब अगली बड़ी रैली के संकेतों पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे आने वाले हफ्तों में बाजार में नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

विदेशी दबाव और नई फसल के बीच खाद्य तेलों के दाम में उतार-चढ़ाव

- अधिकांश तेल-तिलहन के दाम सप्ताह के अंत तक गिरावट के साथ बंद हुए

नई दिल्ली ।

विदेशी बाजारों में पिछले सप्ताह खाद्य तेलों के दाम में गिरावट रही। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की अफवाहों ने भी घरेलू बाजार पर दबाव डाला। अधिकांश तेल-तिलहन के दाम सप्ताह के अंत तक गिरावट के साथ बंद हुए। सरसों का दाम एमसएपी से ऊपर बना हुआ है। नई फसल मंडियों में आने को तैयार है और तेल की मात्रा भी अधिक है। तेल मिलें खरीद मूल्य कम करने का प्रयास कर रही हैं। मौसम खुलने पर आवक बढ़ने से दाम और टूटने की संभावना है। सोयाबीन की उपलब्धता कम होने के कारण तेल संयंत्र पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे। ब्राजील में अच्छी फसल और आगे के सौदे दामों को 8-10 रुपये/किलो नीचे धकेल रहे हैं। परिणामस्वरूप सोयाबीन तेल के दाम में भी गिरावट रही। मूंगफली की मांग अधिक और उपलब्धता कम रहने से दाम में मजबूती बनी रही। जाड़े और कम मांग के कारण पाम और पामोलीन तेल के दाम गिरावट के साथ बंद हुए। सरकार ने आयात शुल्क भी बढ़ाया है, जिससे बाजार में संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है।

सूत्रों ने बताया कि बीते सप्ताह सरसों दाना 40 रुपये की गिरावट के साथ 6,910-6,935 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। दादरी मंडी में बिकने वाला सरसों तेल 50 रुपये की गिरावट के साथ 14,200 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों पक्की और कच्ची घानी तेल का भाव क्रमशः 10-10 रुपये की गिरावट के साथ क्रमशः 2,390-2,490 रुपये और 2,390-2,535 रुपये टिन (15 किलो) पर बंद हुए। समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन दाने और सोयाबीन लूज के थोक भाव क्रमशः 250-250 रुपये की गिरावट के साथ क्रमशः 5,350-5,400 रुपये और 4,950-5,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुए। इसी प्रकार दिल्ली में सोयाबीन तेल 250 रुपये की गिरावट के साथ 14,350 रुपये प्रति क्विंटल, इंदौर में सोयाबीन तेल 250 रुपये की गिरावट के साथ 13,950 रुपये और सोयाबीन डीगम तेल का दाम 300 रुपये की गिरावट के साथ 11,200 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। उन्होंने कहा कि बाजार के आम रुख के उलट, जाड़े में साबुत खाने और अच्छी गुणवत्ता के खाद्य तेल की मांग बढ़ने से अकेले मूंगफली तेल-तिलहन की कीमतों में सुधार देखा गया। मूंगफली तिलहन 125 रुपये सुधरकर 7,125-7,500 रुपये क्विंटल, मूंगफली तेल गुजरात 400 रुपये के सुधार के साथ 17,500 रुपये क्विंटल और मूंगफली साल्वेंट रिफाइंड तेल 50 रुपये के सुधार के साथ 2,775-3,075 रुपये प्रति टिन पर बंद हुआ। बीते सप्ताह में सीपीओ तेल का दाम 175 रुपये की गिरावट के साथ 11,725 रुपये प्रति क्विंटल, पामोलीन दिल्ली का भाव 200 रुपये की गिरावट के साथ 13,625 रुपये प्रति क्विंटल तथा पामोलीन एक्स कांडला तेल का भाव 200 रुपये की गिरावट के साथ 12,525 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।गिरावट के आम रुख के बीच, समीक्षाधीन सप्ताह में बिनौला तेल का दाम भी 250 रुपये की गिरावट के साथ 13,050 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

हीरो मोटोकॉर्प का स्कूटर, प्रीमियम बाइक और ईवी पर फोकस

- चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 16.97 लाख मोटरसाइकिल और स्कूटर बेचे गए

नई दिल्ली ।

देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प अब उन क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, जहां इसकी हिस्सेदारी अभी कम है। कंपनी के एक अे धिकारी ने कहा कि स्कूटर, प्रीमियम मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) में विस्तार की बड़ी संभावना है। उनका कहना था कि तेजी से बढ़ते इन सेगमेंट में अवसरों का पूरा फायदा उठाना कंपनी की प्राथमिकता है। हीरो मोटोकॉर्प अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपने कदम मजबूत करने का इरादा रखती है। इसके अलावा, कलपुर्ज़ और एक्सेसरीज (स्पेयर पाट्‌र्स और सहायक उपकरण) के कारोबार में विस्तार कर कंपनी अपने राजस्व के नए स्रोत खोज रही है। दिसंबर तिमाही में कंपनी ने 12,487 करोड़ रुपये का राजस्व और 1,275 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 16.97 लाख मोटरसाइकिल और स्कूटर बेचे गए, जो पिछले साल इसी अवधि की 14.64 लाख इकाई की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है। अे धिकारी ने बताया कि कंपनी अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और लचीला बनाए रखने पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि कलपुर्ज़ की कमी और भू-राजनीतिक चुनौतियां पूरी तरह समाप्त

नहीं हुई हैं, लेकिन कंपनी इन परिस्थितियों से अच्छी तरह निपट रही है। हीरो मोटोकॉर्प प्रीमियम स्कूटर, ईवी पोर्टफोलियो और 'हीरो 2.0' व 'प्रीमिया' के माध्यम से ग्राहक सेवा में सुधार और निवेश जारी रखेगी। कंपनी की रणनीति स्पष्ट हैः सिर्फ बिक्री बढ़ाना ही नहीं, बल्कि उच्च-मूल्य वाले सेगमेंट और वैश्विक विस्तार में भी अपनी पकड़ मजबूत करना।

सुप्रीम कोर्ट की रेरा पर सख्ती, रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ेगी जवाबदेही

- निवेशक और खरीदार जिम्मेदार और संगठित कंपनियों की ओर आकर्षित होंगे

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के कामकाज पर गंभीर टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि कई राज्यों में प्राधिकरण डिफॉल्टर बिल्डर्स को राहत देते दिख रहे हैं, जबकि उनका मुख्य उद्देश्य खरीदारों के हितों की सुरक्षा करना है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि यदि प्राधिकरण प्रभावी ढंग से कार्य नहीं करते, तो रेरा के अस्तित्व पर पुनर्विचार आवश्यक हो सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अब केवल कानून का होना पर्याप्त नहीं है; उसका ईमानदार और कड़ा प्रवर्तन जरूरी है। राज्यों के रेरा प्राधिकरणों को परियोजनाओं की समयसीमा की निगरानी, एस्क्रो खातों का पारदर्शी उपयोग और लंबित शिकायतों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना होगा। इससे खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा और बाजार में पारदर्शिता आएगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद रेरा प्राधिकरणों पर दबाव बढ़ेगा कि शिकायतों का निपटारा तेजी और पारदर्शिता के साथ करें। इससे घर खरीदारों के अधिकार सुरक्षित होंगे और उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी जाएगी। विश्लेषकों के अनुसार, सख्त प्रवर्तन छोटे या कमजोर डेवलपर्स के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है।

वेदांता ने नायरा को घरेलू कच्चे तेल की आपूर्ति रोकी

- नायरा में रोसनेफ्ट समेत कई रूसी कंपनियों का स्वामित्व है

नई दिल्ली ।

रूस के अलावा दुनिया के अन्य देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति बंद होने के बाद रोसनेफ्ट के समर्थन वाली वाली भारतीय रिफाइनरी कंपनी नायरा एनर्जी को घरेलू बाजार में भी कच्चा तेल मिलना बंद हो गया है। सूत्रों के मुताबिक वेदांता लिमिटेड की केयर्न ऑयल एंड गैस ने पाबंदियों के इस माहौल के बीच नायरा को राजस्थान के अपने तेल क्षेत्र से से कच्चे तेल की आपूर्ति रोक दी है। नायरा में रोसनेफ्ट समेत कई रूसी कंपनियों का स्वामित्व है। राजस्थान से आने वाला कच्चा तेल उसकी कुल जरूरत का लगभग पांच-10 प्रतिशत था। इस आपूर्ति को गुजरात में उसकी दो करोड़ टन सालाना (लगभग 4,00,000 बैरल प्रति दिन) क्षमता वाली वाडिनार रिफाइनरी में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन में बदला जाता था। पिछले साल यूरोपीय संघ और ब्रिटेन द्वारा कंपनी पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद वेदांता लिमिटेड की लंदन स्थित मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज एक प्रतिबंध के दायरे में आने वाली कंपनी के साथ वाणिज्यिक करार के कारण दूसरे पाबंदियों के खतरे को लेकर सावधान हो गई थी। इस मामले की जानकारी रखने वाले दो

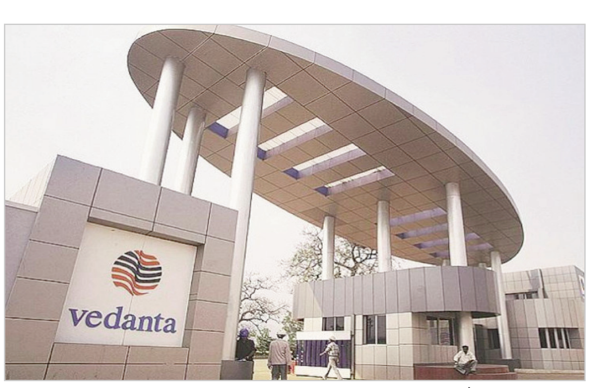

सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि अनुपालन की संभावित दिक्कतों से बचने के लिए वेदांता की केयर्न ऑयल एंड गैस ने नायरा को कच्चे तेल की आपूर्ति रोक दी। केयर्न ऑयल एंड गैस राजस्थान के बाड़मेर तेल क्षेत्र का परिचालन करती है। हालांकि, इस बारे में नायरा को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला।

आईटी सेक्टर निफ्टी 50 में 26 साल के निचले स्तर पर, ऑयल और बीएफसी आगे

- वित्त वर्ष 2025-26 में आईटी शेयरों का प्रदर्शन व्यापक बाजार की तुलना में कमजोर रहा

नई दिल्ली ।

देश के सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र के लिए मौजूदा वित्त वर्ष निराशाजनक रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक जैसी बड़ी आईटी कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट का असर निफ्टी 50 इंडेक्स में भी दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 में आईटी सेक्टर का वेटेज घटकर 8.8 फीसदी रह गया है, जो मार्च 1999 के बाद सबसे कम स्तर है। मार्च 2025 में यह 11.7 फीसदी था, जबकि महामारी के दौरान मार्च 2021 में 16.2 फीसदी तक पहुंचा था। फिलहाल निफ्टी 50 में पांच आईटी कंपनियां हैं, जिनमें सबसे अधिक वेटेज इन्फोसिस (3.97 फीसदी) और टीसीएस (2.27 फीसदी) का है। आईटी सेक्टर अब निफ्टी 50 में तीसरे स्थान पर खिसक गया है। ऑयल और गैस सेक्टर, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल है, ने इसे पीछे छोड़ दिया है। इस सेक्टर की हिस्सेदारी वर्तमान में 9.2 फीसदी है। वहीं बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (बीएफएसआई) सेक्टर का दबदबा बढ़कर 36.5 फीसदी हो गया है। यह पिछले साल 35.6 फीसदी था। वित्त वर्ष 2025-26 में आईटी शेयरों का प्रदर्शन व्यापक बाजार की तुलना में कमजोर रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स, जो देश की 10 प्रमुख आईटी कंपनियों के फ्री फ्लोट मार्केट कैप को ट्रैक करता है, पिछले साल मार्च से अब तक 11.4 फीसदी गिर चुका है।

सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से छह कंप नियों का मार्केट कैप तीन लाख करोड़ से अधिक घटा

- शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर बरकरार रही

मुंबई ।

बीते सप्ताह सेंसेक्स की प्रमुख 10 कंपनियों में से छह के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की गिरावट आई। सबसे ज्यादा नुकसान में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और इन्फोसिस रहीं। समीक्षाधीन सप्ताह में टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारती एयरटेल के बाजार पूंजीकरण में गिरावट आई। वहीं भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो और आईसीआईसीआई बैंक की बाजार हैसियत बढ़ गई। टीसीएस का बाजार मूल्यांकन 90,198.92 करोड़ रुपये घटकर 9,74,043.43 करोड़ रुपये रह गया। इन्फोसिस का मूल्यांकन 70,780.23 करोड़ रुपये के नुकसान के साथ 5,55,287.72 करोड़ रुपये रहा। एचडीएफसी बैंक की बाजार हैसियत 54,627.71 करोड़ रुपये घटकर 13,93,621.92 करोड़ रुपये

और रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्यांकन 41,883 करोड़ रुपये घटकर 19,21,475.79 करोड़ रुपये रह गया। एलआईसी का बाजार पूंजीकरण 23,971.74 करोड़ रुपये घटकर 5,46,226.80 करोड़ रुपये और भारती एयरटेल का मूल्यांकन 19,244.61 करोड़ रुपये घटकर 11,43,044.03 करोड़ रुपये रह गया। इस रुख के विपरीत एसबीआई का मूल्यांकन 1,22,213.38 करोड़ रुपये बढ़कर 11,06,566.44 करोड़ रुपये हो गया। बजाज फाइनेंस की बाजार हैसियत 26,414.44 करोड़ रुपये बढ़कर 6,37,244.64 करोड़ रुपये हो गई। लार्सन एंड टुब्रो का मूल्यांकन 14,483.9 करोड़ रुपये बढ़कर 5,74,028.93 करोड़ रुपये हो गया।

सट्टेबाजी पर लगाम लगाने आरबीआई ने शेयर बाजार से जुड़े कर्ज नियम किए सख्त

1 अप्रैल से लागू होंगे नए निर्देश, नए नियमों का सबसे अधिक असर प्रोपायटरी ट्रेडिंग फर्मों पर पड़ेगा

नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शेयर और कमोडिटी बाजार में बढ़ती सट्टेबाजी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कर्ज नियमों को कड़ा कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल से प्रतिभूति बाजार से जुड़े ब्रोकरों और अन्य मध्यस्थ संस्थानों को दिए जाने वाले सभी ऋण पूरी तरह सुरक्षित (कोलेटरल आधारित) होने चाहिए। अब बैंक ऐसे किसी भी कर्ज की अनुमति नहीं देंगे, जिसका उपयोग ब्रोकर अपनी खुद की प्रोपायटरी ट्रेडिंग या निवेश गतिविधियों में करें। नए नियमों का सबसे अधिक असर प्रोपायटरी ट्रेडिंग फर्मों पर पड़ सकता है। पूंजी की लागत बढ़ने और उधारी सीमित होने से उनकी लाभप्रदता पर दबाव आने की आशंका है। देश के सबसे बड़े शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पिछले वर्ष इक्विटी ऑप्शंस कारोबार में प्रोप फर्मों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक रही, जबकि कैश इक्विटी सेगमेंट में उनकी भागीदारी करीब 30

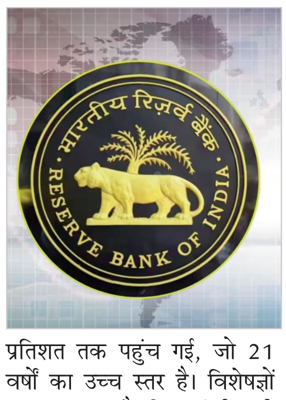

प्रतिशत तक पहुंच गई, जो 21 वर्षों का उच्च स्तर है। विशेषज्ञों का मानना है कि पूंजी की उपलब्धता घटने से ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रभावित हो सकता है। आरबीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि बैंक किसी ब्रोकर की ओर से प्रोप ट्रेड के लिए गारंटी देते हैं, तो वह पूरी तरह सुरक्षित होनी चाहिए। कुल जमानत में कम से कम 50 प्रतिशत नकद अनिवार्य होगा, जबकि शेष हिस्सा नकद समकक्ष या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में स्वीकार किया जाएगा। मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा के तहत दिए जाने वाले ऋण भी अब केवल नकद या अत्यधिक तरल प्रतिभूतियों से सुरक्षित होंगे। यदि शेयर जमानत के रूप में पेश किए जाते हैं, तो उन पर 40 प्रतिशत की छूट (हेयरकट) लागू होगी। केंद्रीय बैंक का यह कदम वित्तीय प्रणाली में जोखिम को सीमित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

टी20 वर्ल्ड कप: जेसन होल्डर और शाई होप का कमाल, वेस्ट इंडीज ने नेपाल को रौंदकर सुपर 8 में मारी एंट्री

मुंबई (एजेंसी)। जेसन होल्डर के चार विकेट और कप्तान शाई होप की 44 गेंदों पर 61 रनों की पारी की बदौलत वेस्ट इंडीज ने रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के 25वें मैच में नेपाल को नौ विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही कैरेबियन टीम सुपर एट में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। नेपाल आधिकारिक तौर पर सुपर एट की दौड़ से बाहर हो गया है। शाई होप की अगुवाई वाली वेस्ट इंडीज ने 134 रनों के मामूली लक्ष्य को महज 15.2 ओवरों में हासिल कर एशियाई टीम पर आसान जीत दर्ज की।

ब्रैंडन किंग (17 गेंदों पर 22 रन) और होप (44 गेंदों पर 61 रन नाबाद) ने पहले विकेट के लिए 43 रनों की साझेदारी की। इसके बाद शिमरोन हेटमायर (32 गेंदों पर 46 रन नाबाद) होप के साथ जुड़े और वेस्ट इंडीज को जीत की ओर ले गए। इससे पहले, टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और स्पिनर अकील हुसैन से गेंदबाजी की शुरुआत की। कुशल भुरटेल और आसिफ शेख ने नेपाल की ओर से पारी की शुरुआत की। नेपाल के लिए शुरुआत बेहद खराब रही क्योंकि मैच के पहले ही ओवर की पांचवीं गेंद पर हुसैन ने कुशल भुरटेल को एक रन पर आउट कर दिया।

कप्तान रोहित पौडेल चौथे ओवर में मात्र पांच रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जब मैथ्यू फोर्डे की गेंद पर पैड पर गेंद लगने से वे एलबीडब्ल्यू हो गए। पावरप्ले में ही नेपाल ने अपना तीसरा विकेट जेसन होल्डर के हाथों गंवा दिया। आसिफ शेख (11) ने शुरुआत में दो चौके लगाए। नेपाल पावरप्ले के अंत तक तीन महत्वपूर्ण विकेट खोकर 22 रन पर ढेर हो गया। पावरप्ले के बाद, शानदार फॉर्म में चल रहे गेंदबाज जेसन होल्डर ने आरिफ शेख को दो रन पर आउट कर दिया। लोकेश बाम के 13 रन पर शमर जोसेफ द्वारा आउट होने के बाद, नेपाल का स्कोर 11वें ओवर में 46-5 था। छठे विकेट के लिए दीपेंद्र सिंह ऐरी और गुलसन झा के बीच 23 रनों की छोटी साझेदारी हुई, जिसके बाद गुलसन 11 रन बनाकर रोस्टन चेस के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए। नेपाल की पारी में दीपेंद्र ही एकमात्र सकारात्मक खिलाड़ी रहे। उन्होंने सोमपाल कामी के साथ सातवें विकेट के लिए 54 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी में अहम भूमिका निभाई। यह साझेदारी तब समाप्त हुई जब दीपेंद्र 47 गेंदों में 58 रन बनाकर होल्डर की गेंद पर आउट हो गए। नेपाल ने अपनी पारी 133/8 के स्कोर पर समाप्त की।

शेल्टन ने सेमीफाइनल थ्रिलर में शापोवालोव को हराया, फ्रिट्ज भी फाइनल में पहुंचे

डलास (एजेंसी)। बेन शेल्टन नेक्सो डलास ओपन में अपने साथी लेफ्टी डेनिस शापोवालोव के बड़े टेस्ट से बच निकले, जहां उन्होंने आखिरी सेट के टाई-ब्रेक में जीत हासिल करके फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सीड वाले खिलाड़ी ने डिफेंडिंग चैंपियन को 4-6, 6-4, 7-6(4) से हराया।

दूसरे सीड वाले शेल्टन ने पूरे मुकाबले में दबाव में शानदार हिम्मत दिखाई। उन्होंने 11 में से 10 ब्रेक पॉइंट बचाए, जिसमें दूसरे सेट में 2-2 पर क्लच वॉली से एक जरूरी सेव और तीसरे सेट में 5-5 पर एक और सेव शामिल है। इस जीत के साथ, उन्होंने जोड़ी की हेड टू हेड सीरीज में 4-0 की बढ़त बना ली। फाइनल में शेल्टन का मुकाबला टॉप सीड टेलर फ्रिट्ज से होगा। 2018 के बाद से यह टूर्नामेंट में टॉप दो सीड के बीच पहला फाइनल होगा, जब टॉप सीड केविन एंडरसन ने न्यूयॉर्क में दूसरे सीड सैम क्वेरी को हराया था, जहां पहले यह टूर्नामेंट हुआ था।

फ्रिट्ज ने शनिवार को सेमीफाइनल में फिर से वापसी कर रहे मारिन सिलिच का सिलसिला रोक दिया। थोड़े अंतर से तय हुए मैच में, टॉप सीड ने अपना धैर्य बनाए रखा और क्रोएशियाई खिलाड़ी को दो घंटे, दो मिनट के रोमांचक मुकाबले में 7-6(5), 7-6(3) से हराया, और 37 साल के खिलाड़ी को 22 एस से हराया।

फ्रिट्ज ने कोर्ट पर अपने इंटरव्यू में कहा, %बस बहुत शांत सर्विंग। मुझे लगता है कि जब मैं शांत और रिलैक्स महसूस करता हूं, तो यही सबसे बड़ी बात है, मैं अच्छी सर्व करता हूं।% दोनों खिलाड़ियों ने बिना ब्रेक वाले मैच में बड़ी डिलीवरी से दबदबा बनाया। फ्रिट्ज़ को ब्रेक पॉइंट का सामना नहीं करना पड़ा और उन्होंने सिलिच के 16 के मुकाबले 22 एस मारे, जिसमें पहले सेट के टाई-ब्रेक में चार शामिल थे।

हालांकि वह अपने पांच ब्रेक-पॉइंट मौकों में से किसी को भी भुना नहीं पाए, लेकिन सर्व पर फ्रिट्ज के शांत स्वभाव ने आखिरकार फर्क पैदा किया क्योंकि उन्होंने अपने पहले सर्व पॉइंट्स का 86 प्रतिशत (48/56) जीता। इस जीत के साथ फ्रिट्ज ने जोड़ी की हेड2हेड सीरीज़ में 3-1 की बढ़त बना ली और 2024 में यूएस ओपन के फ़ाइनल में पहुंचने के बाद घरेलू मैदान पर अपने पहले फाइनल में पहुंच गए।

अरुंधति रेड्डी की घातक गेंदबाजी से भारत की जीत, सीरीज में 1-0 की बढ़त

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 रन (DLS नियम) से जीत दर्ज की। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारतीय गेंदबाजों ने 133 रन पर समेट दिया, जबकि दो ओवर अभी बाकी थे।

अरुंधति रेड्डी मैच की स्टार रहीं। उन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट झटके और अहम मौकों पर ऑस्ट्रेलिया की पारी को झकझोर दिया। रेणुका सिंह और श्री चरणी ने भी सधी हुई गेंदबाजी की। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फील्डिंग में शानदार डाइविंग कैच लेकर टीम का हौसला बढ़ाया।

ऑस्ट्रेलिया ने तेज शुरुआत की और तीन ओवर में 22 रन बना लिए, लेकिन बेथ मूनी के आउट होते ही विकेटों का सिलसिला शुरू हो गया। एलिस पेरी और फोएबे लिचफील्ड ने 41 रन की साझेदारी कर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करते हुए लगातार विकेट चटकाए।

80 रन पर पांच विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी। जॉर्जिया वेयरहैम ने थोड़ी देर संघर्ष किया, लेकिन टीम 133 रन पर सिमट गई।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अच्छी शुरुआत की। टीम का स्कोर 50/1 था जब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा।

उपकप्तान स्मृति मंधाना (16*) और जेमिमा रोड्रिग्स (9*) क्रीज पर मौजूद थीं। बारिश के कारण मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका और ष्ठरुस् नियम के तहत भारत को 21 रन से विजेता घोषित किया गया।

टी20 वर्ल्ड कप: श्रीलंका के खिलाफ जीत के इरादे से उतरेगी ऑस्ट्रेलिया

पल्लेकेले(एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया की टीम मेजबान श्रीलंका के खिलाफ सोमवार को यहां होने वाले टी20 विश्व कप ग्रुप बी के अहम मुकाबले में किसी भी हाल में जीत हासिल करना रहेगा। ऑस्ट्रेलिया का लक्ष्य इस मैच को जीतकर सुपर आठ में पहुंचने की अपनी संभावनाएं बनाये रखना रहेगा। पिछले मैच में टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। उससे सबक लेते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मैच में अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को शामिल कर सकती है। पिछले मैच में उसके बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करने में असफल रहे थे। अब उसे सुपर आठ में पहुंचने के लिए इस मैच के साथ ही ओमान के खिलाफ मैच में बड़ी जीत दर्ज करनी होगी।

ऑस्ट्रेलिया अभी ग्रुप बी में अंक तालिका में दो मैचों में दो अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। जिम्बाब्वे के खिलाफ उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज विफल रहे थे जिससे टीम 146 रन ही बना पायी और उसे 23 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। कप्तान मिचेल मार्श चोटिल होने के कारण उस मैच में नहीं खेल पाए थे। वहीं स्मिथ को मार्श के कवर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है उन्हें हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर 15 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम स्मिथ को चोटिल तेज गेंदबाज जोश हेज़लवुड के बाहर होने के कारण उनकी जगह पर शामिल कर सकती है। स्पिन के खिलाफ स्मिथ का अच्छा रिकॉर्ड और उनके आने से बल्लेबाजी बेहतर होगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह राहत की बात है कि ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को पिछले मैच में अपने बाएं हाथ पर लगी चोट से उबरकर वापसी के लिए तैयार हैं।

ऑस्ट्रेलिया को इस बार मिचेल स्टार्क, चोटिल पैट कमिंस और हेज़लवुड की तेज गेंदबाजी तिकड़ी की कमी भी महसूस हो रही है। नाथन एलिस ने अच्छी गेंदबाजी की है पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बेन ड्वार्शियस और जेवियर बार्टलेट विफल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की इस टीम को भारत में हुए 2023 एकदिवसीय विश्व कप के दौरान भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। तब श्रीलंका के खिलाफ मिली जीत ने उनके लिए हालात बदल दिए, जिसके बाद उसने फाइनल सहि नौ मैच जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। उस बात से टीम प्रेरणा लेना चाहेगी।

जिम्बाब्वे से हार के बाद कप्तानी संभाल रहे ट्रैविस हेड ने कहा था, हम पहले भी ऐसी स्थिति का सामना कर चुके हैं। हमने 2023 में कुछ हार और चोटों के कारण पहले भी इस तरह की स्थिति देखी है। हमारे पास यहां कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2023 में भारत में खेल चुके हैं और हम इस स्थिति से निपटने और उस रणनीति का उपयोग करने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी ओर सह-मेजबान श्रीलंका ओमान और आयरलैंड के खिलाफ आसान जीत के साथ ग्रुप में शीर्ष पर है और उसके हौंसले बढ़ हुए हैं। उससे घरेलू धरती पर खेलने का भी लाभ मिलेगा।

उसे हालांकि स्टार स्पिनर वानिंदु हसरंगा की कमी खलेगी। उनकी अनुपस्थिति में श्रीलंका महेश तीक्षना और बाएं हाथ के स्पिनर दुनीत वेलालेज पर काफी हद तक आधारित रहेगा।

हैरी केन ने अपने करियर का 500वां गोल दागा

बर्लिन। इंग्लैंड के स्टार फुटबॉलर हैरी केन ने शनिवार को बायर्न म्यूनिख की तरफ से दो गोल करके अपने देश और विभिन्न क्लबों की तरफ से 500 गोल करने की उपलब्धि हासिल की। केन ने अपने दो गोल में से एक गोल पेनल्टी पर किया। यह पेनल्टी पर किया गया उनका 100वां था। केन के दो गोल की मदद से बायर्न ने वेर्डर ब्रेमेन पर 3-0 से जीत हासिल करके बुंडेसलिगा में अपनी छह अंकों की बढ़त बरकरार रखी। केन ने मैच के बाद कहा, ''अच्छा लग रहा है। 500 गोल तक पहुंचना वाकई गर्व की बात है। इसमें बहुत मेहनत और त्याग लगा है, इसलिए यहां तक पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमेशा की तरह अब अगला मैच ही मायने रखता है।'' केन ने अपना पहला गोल जनवरी 2011 में 17 साल की उम्र में इंग्लैंड के तीसरी श्रेणी के क्लब लेटन ओरिएंट की तरफ से खेलते हुए शेफील्ड वेडनेसडे के खिलाफ किया था। केन को 500 गोल तक पहुंचने के लिए 743 मैचों की जरूरत पड़ी। इस 32 वर्षीय इस फॉरवर्ड ने इंग्लैंड के लिए 112 मैचों में 78 गोल किए हैं।

मार्करम कप्तान के तौर पर सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों में शामिल

अहमदाबाद। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एडेन मार्करम ने टी20 विश्व कप 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में 44 गेंदों में नाबाद 88 रनों की पारी के साथ ही एक अहम उपलब्धि अपने नाम की है।

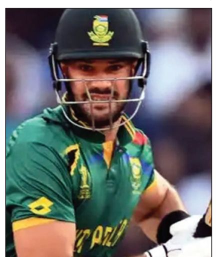

इसी के साथ ही मार्कराम कप्तान के तौर पर सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गये। मार्करम ने अपनी इस पारी में आठ चौके और चार छक्के लगाये। इससे पहले ये रिकार्ड भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के नाम था। इससे दक्षिण अफ्रीका ने ग्रुप डी के इस मैच में जीत के लिए मिले 176 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। मार्करम ने इस मैच में केवल 19 गेंदों में ही पचास रन पूरे कर लिए। ये टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे तेज अर्धशतक है। इस प्रकार उन्होंने रोहित शर्मा के क्लब में प्रवेश किया। रोहित ने साल 2024 टी20 विश्व कप में कप्तान के तौर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 गेंदों में ही अपने पचास रन बना दिये थे। तब रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 गेंदों में 92 रनों की पारी खेली, जिसमें सात चौके और आठ छक्के शामिल हैं। सबसे तेज पचास रन बनाने वाले कप्तानों में श्रीलंका के दासुन शनाका भी हैं। शनाका ने भी ओमान के खिलाफ 19 गेंदों में 50 रन बनाये थे। वहीं मोहम्मद अशरफुल ने 20 और महेला जयवर्धने ने 21 गेंद में अर्धशतक लगाये थे।

टी20 विश्वकप : यूएई के खिलाफ हर हाल में जीत हासिल करने उतरेगी अफगानिस्तान

नई दिल्ली (एजेंसी)। अफगानिस्तान की टीम सोमवार को ग्रुप डी के अहम मुकाबले में अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने उतरेगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में सुपर ओवर में हार के कारण अब उसे अंतिम आठ के लिए अपनी संभावनएं बरकारार रखने ये मैच हर हाल में जीतना होगा। वहीं यूएई ने पिछले मैच में कनाडा को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की थी जिससे उसका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा।

ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड छह और चार अंकों लेकर शीर्ष दो स्थानों पर हैं, ऐसे में यूएई को क्वालीफाई करने इस मैच में जीत हासिल करनी होगी। वहीं अफगानिस्तान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बेहद करीबी हार के बाद ये मैच जीतना चाहेगी। उसे अंतिम आठ में जगह बनाने अपने बचे हुए मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे। इसके अलावा प्रतियोगिता में बने रहने के लिए अन्य मैचों के परिणामों पर भी निर्भर रहना होगा। इससे पहले न्यूजीलैंड ने यूएई को 10 विकेट से हराया था जबकि कनाडा के खिलाफ भी उसे कड़े संघर्ष के बाद जीत मिली थी।

कनाडा के खिलाफ यूएई के शीर्ष और मध्य क्रम के बल्लेबाज विफल रहे थे हालांकि सलामी बल्लेबाज आर्यंश शर्मा के 74 रनों से उसे जीत मिली। इसके अलावा शोएब खान ने 51 रन बनाये। यूएई के बल्लेबाजों के लिए अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान, मुजीब उर रहमान और मोहम्मद नबी का सामना करना कठिन रहेगा। यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम कहना है कि हमें सातवें से 15वें और 16वें ओवर तक बीच के ओवरों में अपनी बल्लेबाजी में सुधार करना होगा।

यूएई की गेंदबाजी इकाई ने कनाडा के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की थी। तेज गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी ने पांच विकेट लिए पर रहमानुल्लाह गुरबाज, गुलबदीन नायब और अजमतुल्लाह उमरजाई जैसे बल्लेबाजों को रोकना उनके लिए आसान नहीं रहेगा। गुरबाज ने पिछले मैच में 42 गेंदों में 84 रन बनाकर बनाकर आक्रामक बल्लेबाजी की थी जो वह अब भी जार रखना चाहेंगे।

दोनो ही टीमें इस प्रकार हैं

अफगानिस्तान- राशिद खान (कप्तान), इब्राहिम जादरान (उपकप्तान), दरविश रसूली, मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, शाहिदुल्लाह, अब्दुल्ला अहमदजई, फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, जियाउर रहमान।

यूएई- मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, आर्यांश शर्मा, ध्रुव पराशर, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मयंक कुमार, मुहम्मद अरफान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, हैदर शाह, रोहिद खान, सोहैब खान, सिमरनजीत सिंह।

आईएसएल की शानदार शुरुआत, मोहन बागान ने केरला ब्लास्टर्स को 2-0 से हराया

कोलकाता। गत चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट्स ने इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) सत्र की दमदार शुरुआत करते हुए शनिवार को यहां केरला ब्लास्टर्स एफसी को 2-0 से मात दी। मोहन बागान के लिए पहला गोल 36वें मिनट में जैमी मैकलारेन ने दागा। मैच के अंतिम क्षणों में दूसरे हाफ के इंजरी टाइम (90+6 मिनट) में टॉम एल्ड्रेड ने गोल कर जीत पक्की कर दी। मैकलारेन को शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। इस बीच, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने बड़ा ऐलान करते हुए पुष्टि की कि इस सत्र से आईएसएल में पहली बार रेलीगेशन प्रणाली लागू की गई है। अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर रहने वाली टीम को दूसरे स्तर की इंडियन फुटबॉल लीग (आईएफएल) में भेजा जाएगा, जबकि आईएफएल की चैंपियन टीम को अगले सत्र में आईएसएल में पदोन्नत किया जाएगा। एआईएफएफ के अनुसार, 12वें आईएसएल सीजन की चैंपियन टीम को अगले सत्र में एएफसी चैंपियंस लीग-2 के प्रारंभिक दौर में प्रवेश मिलेगा। दूसरे स्तर की आई-लीग का नाम बदलकर अब इंडियन फुटबॉल लीग कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत 21 फरवरी से होगी।

भारत-पाकिस्तान मैच में कायम रही 'No Handshake' की परंपरा, सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान कैप्टन को किया इग्नोर!

कोलंबो (एजेंसी)। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत के खिलाफ खेले जा रहे इस महत्वपूर्ण मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुना। हालांकि, इस दौरा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। इस दौरान दोनों कप्तानों के बीच कोई बात भी नहीं हुई है। यह परंपरा पिछले साल दुबई में हुए एशिया कप से चली आ रही है। भारत ने एशिया कप 2025 से इस रुख का पालन किया है और इसे आयु वर्ग के टूर्नामेंटों के साथ-साथ पुरुष और महिला क्रिकेट में भी लागू किया है।

पहलगाम हत्याकांड और उसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर दुबई में आयोजित पिछले साल के एशिया कप के बाद से दोनों पक्षों के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाए हैं। क्या आपको पहले बल्लेबाजी करने में कोई आपत्ति है सवाल के जवाब में टॉस के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि बिलकुल नहीं। हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे। हमने यहां के नतीजे देखे हैं, और हमने पिछले दो मैचों में पहले बल्लेबाजी की है और दोनों में ही जीत हासिल की है, इसलिए हम कुछ भी बदलना नहीं चाहते।

बड़े मौके को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह कहना आसान है कि यह सिर्फ एक और मैच है, लेकिन यह एक बड़ा अवसर है। ये मैच हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन साथ ही, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। यही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, अपने कौशल पर भरोसा रखें, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और खुद पर भरोसा रखें। (क्या फॉर्म मायने रखता है?) यह खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है। किसी भी दिन, अगर आप अच्छा खेल रहे हैं, तो किसी का भी दिन अच्छा हो सकता है। दो बदलाव। अभिषेक शर्मा टीम में आए हैं और कुलदीप यादव अर्शदीप सिंह की जगह आए हैं।

शनिवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा भी इसी तरह सतर्क दिखे। हाथ मिलाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर आगा ने कहा कि हम कल देखेंगे। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खेल भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि क्रिकेट सही भावना से खेला जाना चाहिए। मेरी निजी राय मायने नहीं रखती। लेकिन क्रिकेट उसी तरह खेला जाना चाहिए जैसे हमेशा से खेला जाता रहा है। यह उन पर निर्भर है कि वे क्या करते हैं।

हाथ न मिलाने का रुख सबसे पहले पिछले साल के एशिया कप के दौरान विवाद का मुख्य कारण बना, जब सूर्यकुमार के इनकार पर कथित तौर पर पाकिस्तान और पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में बने रहने से पहले अपने अगले मैच का बहिष्कार करने की धमकी भी दी थी।

विराट से दो बल्ले पाकर गदगद नजर आये अफगानिस्तान के बल्लेबाज गुरबाज

अहमदाबाद। भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुए मुकाबले में अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी से दिल जीतने वाले अफगानिस्तान के बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को दो बल्ले उपहार में दिये हैं। वही गुरबाज ने शानदार तोहफा देने के लिए विराट का आभार जताया और कहा भाई आप महान हैं, हर पीढ़ी आपसे प्रेरणा लेती है।' गुरबाज के इस संदेश से साफ है कि वह विराट का बेहद सम्मान करते हैं। यह पहली बार नहीं है जब कोहली ने अपने बेशकीमती बल्लों को साथी खिलाड़ियों को भेंट किया है। वह आम तौर पर अपने बल्लों को उपहार में देते आये हैं। इसे पहले उन्होंने बांग्लादेश के शाकिब अल हसन के अपने ही साथ खिलाड़ी रजत पाटीदार और रिंकू सिंह को भी उपहार में बल्ले दिये थे। गुरबाज ने इस मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी कर अपनी टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया था। इस बल्लेबाज ने जबरदस्त शॉट लगाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। बल्लेबाजी के दौरान वह निडर दिखे। इस मैच का परिणाम दो सुपर ओवरों में निकला अफगान टीम को हार जरुर झेलनी पड़ी पर गुरबाज ने दिल जीत लिया।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

हैती में सशस्त्र गिरोह लगातार कर रहा बच्चों की भर्ती : यूनिसेफ

पोर्ट-औ-प्रिंस, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की रिपोर्ट के मुताबिक, हैती में सशस्त्र गिरोह लगातार बच्चों की भर्ती कर रहा है। यह संख्या पिछले वर्ष में तिगुनी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, गरीबी और हिंसा के बीच 14 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, इनमें आधे से अधिक बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, गिरोहों के 30 से 50 प्रतिशत सदस्य बच्चे हैं, कुछ की उम्र 9 वर्ष तक है। गिरोह राजधानी पोर्ट-एयू-प्रिंस के 90 फीसदी हिस्से पर काबिज हैं।

तुर्किये में ओनलीफैंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 16 गिरफ्तार

अंकारा, एजेंसी। तुर्किये में ओनलीफैंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस संबंध में लगभग 69 लाख डॉलर की संपत्ति जब्त की गई। यह कार्रवाई आठ प्रांतों में की गई है, इनमें इस्तांबुल, अंकारा और अंताल्या शामिल हैं। जांच में 25 संदिग्धों और दो कंपनियों को निशाना बनाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपियों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री साझा कर ओनलीफैंस और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से कमाई की और कालेधन को संपत्तियों, बिटकॉइन व सोने में निवेश कर सफेद किया।

सिंगापुर में भारतीय पर महिला की हत्या के प्रयास का आरोप

सिंगापुर , एजेंसी। सिंगापुर में एक भारतीय नागरिक पर इंडोनेशियाई महिला की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या के प्रयास का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पन्नीर सेल्वम ने बुधवार सुबह पूर्वी सिंगापुर के सिम्स व्यू इलाके में फजर नूर ऐनी पर हमला। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक, दोनों एक-दूसरे को जानते थे। अदालत में पेश आरोपपत्र में कहा कि सेल्वम की मंशा हत्या करना थी। मामले में दोषी पाए जाने पर उसे आजीवन कारावास या 20 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

अमेरिका-ताइवान में समझौता 99% कम होंगी टैरिफ बाधाएं

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ताइवान की 99 फीसदी टैरिफ बाधाएं कम करने पर सहमत हुआ है। अमेरिकी प्रतिनिधि के अनुसार, ताइवान से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 15 फीसदी या मोस्ट फेवर्ड नेशन दर लागू होगी। अमेरिका ताइवान से कंप्यूटर चिप्स की आपूर्ति पर काफी निर्भर है। इस कारण 2025 के पहले 11 महीनों में लगभग 127 अरब डॉलर का व्यापार घाटा दर्ज हुआ। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन और ताइवान के उप प्रधानमंत्री ली-चियुन चेंग की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

कोलोराडो में विमान हादसा, चार लोगों की मौत

कोलोराडो, एजेंसी। उत्तरी कोलोराडो में स्टीमबोट स्प्रिंग्स के स्की रिसॉर्ट के पास शुक्रवार को एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। संघीय विमानन प्रशासन के मुताबिक, छह सीटों वाला टर्बोप्रॉप विमान एपिक ई1000 रात करीब 12:20 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चार लोग सवार थे। राउट काउंटी के कोरोनर मिच लॉक ने बताया कि घटनास्थल पर ही चारों लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान अज्ञात परिस्थितियों में पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एफएए और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड दोनों ने कहा कि वे दुर्घटना की जांच कर रहे हैं। यह विमान टेनेसी के फ्रैंकलिन स्थित एएलएस एविएशन एलएलसी के नाम पर पंजीकृत है। टेनेसी के व्यावसायिक रिकॉर्ड में कंपनी के बारे में संपर्क करने के लिए किसी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं है।

पेरिस पुलिस ने अधिकारियों पर हमला करने की कोशिश करने वाले शख्स को गोली मार कर किया घायल

पेरिस , एजेंसी। पेरिस पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, हमलावर ने नेपोलियन युग के ऐतिहासिक स्थल पर अज्ञात सैनिकों को श्रद्धांजलि देने वाली चिरस्थायी लौ को पुनः प्रज्वलित करने के समारोह की सुरक्षा कर रहे एक अधिकारी को निशाना बनाया। अधिकारी ने बताया कि एक अन्य अधिकारी ने हमलावर पर गोली चलाई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि इस घटना में कोई भी राहगीर या पुलिस अधिकारी घायल नहीं हुआ। फ्रांस के आतंकवाद विरोधी अभियोजक कार्यालय ने कहा कि वह मामले की जांच कर रहा है और उसने एक जांचकर्ता को घटनास्थल पर भेजा है। आर्क डी ट्रायम्फ पेरिस के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है और यह व्यस्त चैंप्स-एलिसी एवेन्यू के शीर्ष पर स्थित है।

खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश का मामला: भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 24 साल की सजा

न्यूयॉर्क कोर्ट में गुनाह कबूला

न्यूयॉर्क, एजेंसी। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 24 साल की जेल की सजा सुनाई गई। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक निखिल ने शुक्रवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क की कोर्ट में गुनाह कबूल कर लिया है। 29 मई को सजा का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने एक्स पर पोस्ट कर निखिल गुप्ता के अपराध कबूलने की जानकारी दी। एफबीआई के मुताबिक, यह साजिश एक अमेरिकी नागरिक की हत्या के लिए रची गई थी, जिसे अमेरिकी एजेंसियों ने समय रहते नाकाम कर दिया। यूएस अटॉर्नी ऑफिस के बयान के मुताबिक, निखिल गुप्ता उर्फ 'निक' ने सेकंड सुपरसिडिंग इंडिक्टमेंट में लगाए गए तीनों आरोपों को स्वीकार किया है। इन आरोपों में मर्डर-फॉर-हायर, मर्डर-फॉर-हायर की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश शामिल है।

निखिल को यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार किया : पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में निखिल गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक रिपब्लिक पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 14 जून 2024 को निखिल को अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया था। निखिल पर अमेरिका में केस चलाया गया, जहां उसने खुद को निर्दोष बताया था।

अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक, भारत के एक पूर्व अफसर विकास यादव ने निखिल गुप्ता से पन्नू की हत्या की साजिश रचने को कहा था। अमेरिकी न्याय विभाग ने दावा किया है कि भारतीय सरकार के एक कर्मचारी ने निखिल गुप्ता को पन्नू की हत्या के लिए एक हिटमैन की व्यवस्था करने को कहा था। यह आरोप मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में दाखिल इंडिक्टमेंट में लगाया गया था। उस कर्मचारी को आरोपपत्र में सीसी-1 कहा गया है

मई 2023: अमेरिकी प्रॉसिक्यूटर के मुताबिक एक भारतीय अधिकारी (विकास यादव) ने निखिल गुप्ता को हायर किया।

29 मई: निखिल गुप्ता ने किसी ऐसे शख्स की तलाश शुरू की जो पन्नू को मार सके। हालांकि, जिसे पन्नू को मारने के लिए हायर किया गया वो अमेरिका का अंडर कवर एजेंट निकला। कुछ हफ्तों तक निखिल गुप्ता ने इस अंडर कवर एजेंट से पन्नू को मारने के तरीके और कीमत पर चर्चा की।

9 जून: गुप्ता ने पन्नू को मारने के लिए हायर किए गए हिटमैन को एक शख्स के जरिए 15 हजार डॉलर (12 लाख 49 हजार रुपए) का कैश भिजवाया। ये हत्या के लिए एडवांस पेमेंट था। पूरी डील 1 लाख डॉलर (84 लाख रुपए) में हुई थी।

11 जून: भारतीय अधिकारी ने गुप्ता को कहा कि पन्नू को अभी नहीं मरवा सकते हैं। दरअसल, जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। गुप्ता ने भी फोन पर कहा था कि 10 दिनों तक कुछ नहीं किया जा सकता है, नहीं तो प्रदर्शन शुरू हुए जाएंगे।

18 जून: कनाडा में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई।

19 जून: गुप्ता निज्जर की हत्या का वीडियो अमेरिका में पन्नू की हत्या के लिए हायर किए हिटमैन को भेजा और कहा कि ये अच्छी खबर है, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

24 जून से 29 जून: गुप्ता ने पन्नू का मारने का प्लान आगे बढ़वाया। पन्नू की निगरानी शुरू हुई।

30 जून: गुप्ता को चेक रिपब्लिक में अमेरिका के कहने पर हिरासत में ले लिया गया।

कौन है गुरपतवंत सिंह पन्नू : गुरपतवंत सिंह पन्नू 'सिख फॉर जस्टिस' नामक संगठन का जनरल काउंसल है, जो अमेरिका में सक्रिय है। हाल के महीनों में पन्नू ने भारत विरोधी गतिविधियों को तेज किया है, जिसमें अमेरिकी शहरों में खालिस्तान जनमत संग्रह आयोजित करना, एयर इंडिया के बहिष्कार के वीडियो जारी करना और भारत विरोधी हरकतों के लिए इनामों की घोषणा करना शामिल है। इन गतिविधियों के कारण भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पन्नू के खिलाफ आतंकवाद से संबंधित नए मामले दर्ज किए हैं।

अमेरिकी सेना का कैरेबियन सागर में एक और बोट पर हमला, 3 की मौत

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करी के आरोप में शुक्रवार को एक और नाव पर हमला किया है। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। अमेरिकी सदर्न कमांड के मुताबिक नाव कथित तौर पर ड्रग तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रही थी। यह हमला किया गया। अमेरिकी सदर्न कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह नाव कैरेबियन में 'नार्को-ट्रैफिकिंग रूट' पर चल रही थी और ड्रग तस्करी में शामिल थी। कमांड ने बताया कि हमले में नाव सवार तीन लोग मारे गए। पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया गया है। वीडियो में एक नाव पानी में चलते हुए दिखती है, जिसके बाद वह धमाके के साथ आग की लपटों में घिर जाती है। यह हमला ट्रम्प प्रशासन की उस कार्रवाई का हिस्सा है, जिसमें कथित ड्रग तस्करी में शामिल नावों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले साल सितंबर से अब तक कैरेबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में कम से कम 38 हमले किए गए हैं। इन हमलों में अब तक कुल 133 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पिछले हफ्ते कहा था कि क्षेत्र के कुछ बड़े कार्टेल ड्रग तस्करों ने हाल की सैन्य कार्रवाइयों के कारण अनिश्चितकाल के लिए नशीले पदार्थों का कारोबार बंद करने का फैसला किया है। हालांकि, हेगसेथ ने अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर किए गए इस दावे के समर्थन में कोई सबूत शेयर नहीं किया। ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका लैटिन अमेरिका के ड्रग कार्टेल के साथ सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में है। उन्होंने इन हमलों को ड्रग्स की सप्लाई रोकने के लिए जरूरी कदम बताया है। हमले का वीडियो साझा करते हुए अमेरिकी सदर्न कमांड ने सोशल मीडिया पर बताया कि 13 फरवरी को कमांडर जनरल फ्रांसिस एल. डोनोवन के निर्देश पर जॉइंट टास्क फोर्स सदर्न स्पीयर ने नामित आतंकवादी संगठनों द्वारा संचालित एक पोत पर घातक सैन्य हमला किया।

पोस्ट में आगे कहा गया कि खुफिया जानकारी से पुष्टि हुई कि पोत कैरिबियाई सागर में मादक पदार्थों की तस्करी के मार्गों से गुजर रहा था और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। इस कार्रवाई में तीन तस्कर मारे गए। अमेरिकी सेना का कोई भी जवान घायल नहीं हुआ।

पेंपा सेरिंग फिर बने निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री

ल्हासा, एजेंसी। निर्वासित तिब्बती सरकार में निवर्तमान सिक्योंग (प्रधानमंत्री) पेंपा सेरिंग को दूसरी बार सरकार चलाने का मौका मिलेगा। प्रथम चरण के मतदान में ही उन्हें सिक्योंग (प्रधानमंत्री) चुन लिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त लोबसांग येशी ने शुक्रवार को मैक्लोडगंज में घोषणा की कि चुनाव नियमों और विनियमों के अनुच्छेद 67(4) के तहत यदि किसी उम्मीदवार को प्रारंभिक चुनाव में कुल मतों का 60 फीसदी से अधिक प्राप्त होता है, तो अंतिम दौर का चुनाव नहीं होगा और वह उम्मीदवार सिक्योंग के रूप में निर्वाचित घोषित होगा। इन्हीं नियमों के अनुसार पेंपा सेरिंग को सिक्योंग के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया है। उन्हें कुल मतों का 61.025% प्राप्त हुआ। एक फरवरी को हुए प्रारंभिक चरण के मतदान में कुल 51,140 तिब्बतियों ने मतदान किया। इसमें कुल 103 उम्मीदवारों ने भाग लिया। वर्तमान सिक्योंग पेंपा सेरिंग ने 31,225 वोट, केल्सग दोरजी औकातसंग और सेरिंग फुन्त्सोक ने क्रमशः 17,843 और 159 वोट प्राप्त किए। बता दें कि पेंपा सेरिंग मई 2021 के चुनाव में 34,348 मत प्राप्त कर पहली बार निर्वासित तिब्बत सरकार के सिक्योंग बने थे। चुनाव आयोग ने इस मौके पर निर्वासित तिब्बती संसद के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसमें तिब्बत के तीन पारंपरिक प्रांतों से 30 उम्मीदवार, तिब्बती बौद्ध धर्म और बोन धर्म के चार स्कूलों से 6 उम्मीदवार, उत्तर-दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से 6-6 उम्मीदवार और ऑस्ट्रेलिया (भारत, नेपाल और भूटान को छोड़कर) से 3 उम्मीदवार शामिल हैं। चुनाव आयुक्त ने यह भी घोषणा की है कि 18वें तिब्बती संसद-इन-एग्जाइल के उम्मीदवारों को 27 फरवरी 2026 तक अपने नामांकन की पुष्टि करनी होगी। जो उम्मीदवार नामांकन वापस लेना चाहते हैं, उन्हें 28 फरवरी तक चुनाव आयोग को एक लिखित अनुरोध सौंपना होगा।

जेफ्री एपस्टीन की मौत खुदकुशी नहीं हत्या, पोस्टमॉर्टम के दौरान मौजूद डॉक्टर का दावा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन को लेकर लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं उसकी मौत अब भी रहस्य बनी हुई है। 2019 में गिरफ्तारी के बाद न्यूयॉर्क की जेल में उसकी मौत हो गी थी। एपस्टीन की पोस्ट मॉर्टम देखने के बाद फरेंसिक पैथलॉजिस्ट डॉ. मिशेल बाडेन ने कहा कि रिपोर्ट पर गौर करें तो एपस्टीन की मौत फांसी लगाकर नहीं हुई थी बल्कि गला घोंटा गया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि उसकी मौत खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या थी।

बाडेन ने द टेलिग्राफ को दिए इंटरव्यू में कहा, मेरे विचार से जेफ्री एपस्टीन की मौत गला घोंटने की वजह से हुई थी। इस मामले में और जांच होनी चाहिए तभी असली वजह का पता चल पाएगा। बता दें कि न्यूयॉर्क की जेल में जेफ्री एपस्टीन को मृत पाया गया था। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनर ने इसे खुदकुशी बताया था। बाडेन ने खुद ऑटोप्सी नहीं की थी लेकिन ऑब्जर्वर के तौर पर उस वक्त वह मौजूद थे।

उन्होंने कहा, ऑटोप्सी करने वाले दोनों ही एग्जामिनर इस बार पर हमसत थे कि मौत के असली कारण का पता लगाने के लिए और जांच की जरूरत है। उन्होंने बताया कि एपस्टीन की मौत के पांच दिन बाद ही सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया था। उस समय की चीफ मेडिकलएग्जीमिनर डॉ. बारबारा सैंपसन ने इसे खुदकुशी बताया था।

उन्होंने यह भी बताया की सैंपसन पोस्टमॉर्टम के दौरान वहां मौजूद भी नहीं थीं। जेफ्री एपस्टीन के गले में तीन निशान पाए गए थे। दो आगे की तरफ और एक पीछे की ओर। इसकेअलावा तीन जगह से गर्दन में फ्रैक्चर हुआ था। डॉ. बदान ने कहा कि उन्होंने अपने करियर में इस तरह के फ्रैक्चर फांसी लगाने के केस में कभी नहीं देखे।

अगस्त 2019 में भी उन्होंने फॉक्स न्यूज को बताया था कि यह खुदकुशी से ज्यादा हत्या का माममला लगता है। एपस्टीन के वकील ने भी कहा था कि वह एग्जामिनर की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं। 2023 की एक अमेरिकी न्याय विभाग की रिपोर्ट में क हा गया था कि न्यूयॉर्क की जेल में सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। यह भी पाया गया था कि एपस्टीन की सेल में एक से ज्यादा कंबल, चद्दर और कपड़े मौजूद थे। एपस्टीन की मौत से एक दिन पहले ही उसके साथ बंद अन्य कैदियों को अलग शिफ्ट कर दिया गया था। एपस्टीन का रोज होने वाला वेलनेस टेस्ट भी उस दिन रात 10 बजकर 40 मिनट तक नहीं किया गया था जो कि 8 बजे ही हो जाना चाहिए था। चेकअप की फर्जी रिपोर्ट लगा दी जाती थी। अगली ही सुबह गार्ड्स ने बताया कि एपस्टीनकी मौत हो गई है और उसकी गर्दन के चारों ओर कपड़े का फंदा पड़ा हुआ हे। गार्ड्स ने फंदा हटाया और उसे सीपीआर देने की कोशिश की और फिर अस्पताल ले गए जहांएपस्टीन को मृत घोषित कर दिया गया।

जर्मन चांसलर मर्ज बोले- यूरोप की आजादी की गारंटी नहीं

म्यूनिख, एजेंसी। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि यूरोप की आजादी की अब गारंटी नहीं है। मर्ज के मुताबिक यूरोप अब यह मानकर नहीं चल सकता कि उसे अपने-आप सुरक्षा मिलती रहेगी। म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मर्ज ने माना कि यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में गहरी दरार आ गई है। उन्होंने कहा कि नियमों से चलने वाली दुनिया खत्म हो गई है, वैश्विक व्यवस्था अब उस रूप में मौजूद नहीं रही। मर्ज ने कहा कि दुनिया अब बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से चल रही है। सम्मेलन में कई यूरोपीय नेता और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद रहे।

सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी व्यवस्था खत्म हुई : मर्ज ने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वैश्विक व्यवस्था बनी थी, वह अब खत्म हो गई है। उन्होंने बताया कि उस समय देश आपसी नियमों और समझ के आधार पर काम करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मर्ज ने कहा कि ऐसे माहौल में यूरोप यह मानकर नहीं चल सकता कि उसकी सुरक्षा और आजादी अपने-आप बनी रहेगी। यूरोपीय देशों को अब ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। जरूरत पड़े तो त्याग भी करना होगा और अपनी रक्षा व अर्थव्यवस्था खुद मजबूत करनी होगी। मर्ज के मुताबिक, अब फैसले साझा नियमों से नहीं, बल्कि ताकत और अपने-अपने हितों के आधार पर लिए जा रहे हैं।

मर्ज बोले- अमेरिका भी अकेले नहीं चल सकता : मर्ज ने कहा कि आज की दुनिया में अमेरिका भी अकेले नहीं चल सकता। उनके मुताबिक, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई भी बड़ी ताकत अपने दम पर हर चुनौती का सामना नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अमेरिका को भी सहयोगियों की जरूरत है। सुरक्षा, रक्षा, तकनीक और व्यापार जैसे बड़े मुद्दों पर साझेदारी जरूरी है। सिर्फ ताकत के भरोसे आगे बढ़ना अब संभव नहीं है। मर्ज ने साफ किया कि नाटो सिर्फ यूरोप के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए भी फायदेमंद है। यह गठबंधन दोनों पक्षों को मजबूत बनाता है। इसलिए उन्होंने कहा, 'आइए, हम मिलकर ट्रांस-अटलांटिक भरोसे को फिर से मजबूत करें। मर्ज के मुताबिक, यूरोप नाटो के भीतर ही एक मजबूत ताकत बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, ताकि साझेदारी बराबरी की हो। उन्होंने यह भी माना कि

मर्ज ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस को निशाना बनाया : मर्ज ने पिछले साल म्यूनिख में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान का जिक्र करते हुए उन पर खुलकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'एमएजीए आंदोलन की सांस्कृतिक लड़ाई हमारी नहीं है।' पिछले साल म्यूनिख सम्मेलन में जेडी वेंस ने यूरोप में अभिव्यक्ति की आजादी, आप्रवासन और पारंपरिक मूल्यों से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि यूरोप अपने मूल्यों से दूर जा रहा है और कुछ देशों में फ्री स्पीच सीमित हो रही है। उनके बयान को यूरोपीय नीतियों की आलोचना के तौर पर देखा गया था। मर्ज ने उसी पर जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका की 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (एमएजीए) राजनीति और उससे जुड़ी सांस्कृतिक बहसें यूरोप की नहीं हैं। उन्होंने साफ किया कि यूरोप में अभिव्यक्ति की आजादी है।

ईरान पर हमले की पूरी तैयार में डोनाल्ड ट्रंप, बता दिया युद्धपोत भेजने के पीछे का इरादा

वाशिंगटन, एजेंसी। ईरान से तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कन्फर्म कर दिया है कि वह अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरे लाव लश्कर के साथ मध्य एशिया भेज रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जरूर चल रही है लेकिन परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव कम नहीं हो रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सैन्या कार्रवाई की धमकी दी है। अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड कैरियर को लेकर जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह तोड़ी ही देर में रवाना होने वाला है। अगर ईरान के साथ मसझौता नहीं होता है तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गेराल्ड के साथ ही यूएसएस अब्राहम लिंकन शिप को भी रवाना किया गया है।

ईरान में विरोध प्रदर्शन के बाद बढ़ गई है तनातनी : ईरान में विरोध प्रदर्शन और फिर खामेनेई द्वारा प्रदर्शनकारियों के दमन को लेकर दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने कहा है कि अगर परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान अमेरिका की बात नहीं मानता है तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गाइडेड मिसाइल से लैस यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही अरब सागर में मौजूद है। पिछले ही सप्ताह ईरान के एक ड्रोन को इसी युद्धपोत पर से ही मार गिराया गया था।

वेनेजुएला में अभियान को अंजाम देने गया था गेराल्ड आर फोर्ड : यूएसएस गेराल्ड फोर्ड युद्धपोत वेनेजुएला में अभियान को अंजाम देने गया था और तब से वहीं था। अब यहां से सीधे वह मध्य एशिया की ओर रवाना कर दिया गया है। बता दें कि दोनों देशों ने पिछले सप्ताह ओमान में बातचीत की थी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर समझौता नहीं होता है तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय ईरान के साथ परमाणु वार्ता में गतिरोध और क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच वाशिंगटन की सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर लिया गया है। यह युद्धपोत अब फारस की खाड़ी और अरब सागर क्षेत्र में पहले से मौजूद 'यूएसएस अब्राहम लिंकन' और उसके सहायक बेड़े के साथ शामिल होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि दो विमानवाहक पोतों की एक साथ मौजूदगी इस क्षेत्र में वाशिंगटन की नौसैनिक ताकत को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा देगी।

अमेरिकी सांसदों ने अप्रैल में ट्रंप-शी की मुलाकात से पहले क्वाड समिट की मांग की

वॉशिंगटन , एजेंसी। दो वरिष्ठ अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप सरकार से अप्रैल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली मीटिंग से पहले क्वाड नेताओं की समिट बुलाने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे बीजिंग के साथ डील करने में वॉशिंगटन की पकड़ मजबूत होगी। अमेरिकी सांसद टिम केन (डी-वीए) और पीट रिकेट्स (आर-एनई) दोनों सीनेट विदेश मामलों के कमेटी के सदस्य हैं। दोनों सांसदों ने इस संबंध में मार्को रुबियो को चिट्ठी लिखी, जिसमें सरकार को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान को शामिल करते हुए क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (क्वाड) के अगले वर्जन को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया। बता दें, इस बार क्वाड समिट की मेजबानी भारत करने वाला है। यह असल में 2025 में भारत में होने वाला था। ट्रंप समेत सभी चार देशों ने भारत क्वाड समिट में शामिल होने की प्रतिबद्धता जताई है। सीनेटरों ने लिखा, 'चीन के साथ जबरदस्त रणनीतिक कॉम्पिटिशन के इस अहम पल में, क्वाड लीडर्स समिट बुलाने से लीडिंग हिंद-प्रशांत लोकतंत्र के बीच एकता, पक्के इरादे और रणनीतिक तालमेल का साफ संकेत जाएगा। अप्रैल में शी जिनपिंग के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की तय मीटिंग से पहले क्वाड समिट करना, राष्ट्रपति के बीजिंग दौरे से पहले हिंद-प्रशांत में अमेरिकी नेतृत्व का एक अहम प्रदर्शन होगा। पहले एक सफल क्वाड समिट राष्ट्रपति ट्रंप को ज्यादा फायदे की स्थिति से जुड़ने का मौका देगा। सांसदों ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रंप के बीजिंग दौरे से पहले होने वाली मीटिंग डिप्लोमैटिक माहौल को आकार देगी। उन्होंने लिखा, 'राष्ट्रपति ट्रंप की ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने में हाल की सफलताओं ने क्वाड के जरिए फिर से मिलकर काम करने का माहौल तैयार किया है। सांसदों ने चिट्ठी में भारत के साथ ट्रेड डील की घोषणा का भी जिक्र किया और कहा कि यह भारत और पूरे हिंद-प्रशांत में रणनीतिक और रक्षा सहयोग को काफी गहरा करने की नींव रखता है।' आम चिंताओं पर जोर देते हुए सांसदों ने लिखा, 'चारों क्वाड साझेदारों को एक जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सप्लाई चेन की कमजोरियां, जरूरी मिनरल्स पर रोक, आजाद और खुले हिंद-प्रशांत के लिए खतरे और नई तकनीक पर बढ़ता कॉम्पिटिशन शामिल हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'चीन ने खास तौर पर जापान पर डिप्लोमैटिक दबाव, सैन्य धमकी और आर्थिक दबाव बढ़ाया है, जिससे इलाके की स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय नियमों को खतरा है।' सांसदों ने कहा, 'क्वाड इन चुनौतियों का सामना करने और ट्रंप की 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में बताए गए कई मकसदों को आगे बढ़ाने के लिए खास स्थिति में है, जिसमें पिछली सरकार की सफलताओं पर काम करना शामिल है, जिसमें सहयोगी देशों की रोकथाम को मजबूत करना, दुश्मनों पर रणनीतिक निर्भरता कम करना, तकनीकी नेतृत्व की सुरक्षा करना और नेविगेशन की आजादी को बनाए रखना शामिल है।'

सांसदों ने आखिर में लिखा, 'हम अमेरिकी डिप्लोमेसी के इस अहम पल में क्वाड को मजबूत करने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं और आपसे क्वाड लीडर्स समिट और उसके बाद विदेश मंत्री और वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आयोजित करने को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं। ऐसा करने से अमेरिकी नेतृत्व मजबूत होगा, हमारे सबसे करीबी साझेदार मजबूत होंगे और यह सुनिश्चित होगा कि बीजिंग के साथ भविष्य का जुड़ाव एकता, ताकत और रणनीतिक दूरदर्शिता पर आधारित हो।'

उन्होंने 13 मार्च, 2026 तक क्वाड के लिए सरकार के दृष्टिकोण और प्राथमिकता पर चर्चा करने के लिए एक ब्रीफिंग का भी अनुरोध किया। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया वाला क्वाड पिछले दस सालों में हिंद-प्रशांत सुरक्षा, मजबूत सप्लाई चेन, नई तकनीक और समुद्री सहयोग पर तालमेल के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है। भारत ने सीमा पर तनाव और बड़े क्षेत्रीय मुकाबले के बीच चीन के साथ अपने मुश्किल संबंध को संतुलित करते हुए लगातार एक आजाद और खुले हिंद-प्रशांत का साथ दिया है।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ्सेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

वार-पलटवार: एपस्टीन फाइल्स पर भाजपा ने सिब्बल को घेरा, राहुल गांधी से मांगा जवाब

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका के बदनाम फाइनेंशर और यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी फाइलों के सार्वजनिक होने के बाद भारत के राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल आ गया है। इस मामले ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक नया मोर्चा खोल दिया है, जहां दोनों दल एक-दूसरे पर एपस्टीन से संबंधों के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। शुरुआत में कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को निशाने पर लिया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पर सीधा हमला बोला है।

भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी से जवाब मांगते हुए दावा किया है कि कपिल सिब्बल को एक ऐसे कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया था, जिसे कथित तौर पर जेफ्री एपस्टीन ने फंड किया था। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि साल 2010 में सिब्बल को जो सम्मान मिला, उसका संबंध एपस्टीन की फंडिंग से था। उन्होंने यह भी कहा कि सिब्बल लंबे समय तक गांधी परिवार के करीबी रहे हैं और कांग्रेस की विदेश इकाई के प्रमुख सैम पित्रोदा भी उसी समूह से जुड़े थे। हालांकि, कपिल सिब्बल ने इन दावों को पूरी तरह से बकवास बताते हुए खारिज कर दिया है। कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभालते हुए प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2010 में जब सिब्बल को पुरस्कार दिया गया, तब वह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे। उन्हें यह सम्मान शिक्षा में वैश्विक सहयोग के प्रति उनके दृढ़ समर्थन के लिए दिया गया था और इसका जेफ्री एपस्टीन या उसके किसी संदिग्ध नेटवर्क से कोई लेना-देना नहीं है। गौरतलब है कि कपिल सिब्बल ने 2022 में कांग्रेस छोड़ दी थी और वर्तमान में वह समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा सांसद हैं।

इस विवाद की जड़ें तब गहरी हुईं जब एपस्टीन फाइल्स में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम सामने आया। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए पुरी के इस्तीफे की मांग की और आरोप लगाया कि वह तथ्यों को लेकर झूठ बोल रहे हैं। वहीं, हरदीप सिंह पुरी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पेशेवर काम के सिलसिले में उनकी एपस्टीन से सामान्य जान-पहचान थी, लेकिन एपस्टीन के निजी कृत्यों या अपराधों से उनका कोई सरोकार नहीं रहा है।कुल मिलाकर, सात समंदर पार के एक अपराधी की फाइलों ने भारत में राजनीतिक नैतिकता की बहस को तेज कर दिया है। जहां भाजपा इसे कांग्रेस के पुराने रसूखदारों के अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जोड़ रही है, वहीं कांग्रेस इसे वर्तमान सरकार के मंत्रियों की जवाबदेही का प्रश्न बना रही है। दोनों ही दल अब इस अंतरराष्ट्रीय विवाद के जरिए एक-दूसरे की छवि धूमिल करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं।

शिरडी में साईं बाबा और महादेव की एक साथ पूजा, भक्तों के लिए 13 हज़ार किलो साबूदाने की खिचड़ी

शिरडी(एजेंसी)। रविवार को महाराष्ट्र समेत पूरे देश में महाशिवरात्रि बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। अलग-अलग महादेव मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं महाराष्ट्र के शिरडी में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। महाशिवरात्रि के अवसर पर साईं बाबा के दर्शन के लिए हज़ारों भक्त जमा हुए। साईं बाबा संस्थान की तरफ से साईं बाबा की समाधि के पास देवाधि देव महादेव की तस्वीर लगाई गई है ताकि भक्त साईं बाबा के साथ भोलेनाथ शंकर के भी दर्शन कर सकें। साथ ही शिरडी में बड़ी संख्या में भक्तों के आने की संभावना और व्रत का दिन होने के कारण, साईं बाबा संस्थान के साईं प्रसादालय में 13 हज़ार किलो साबूदाने की खिचड़ी तैयार की गई। शिरडी आने वाले भक्तों को प्रसादालय में दिन भर साबूदाना खिचड़ी और झिरका प्रसाद परोसा जा रहा था। साईं बाबा संस्थान के प्रसादालय में खिचड़ी बनाने के लिए 5,500 किलो साबूदाना, 4,000किलो मूंगफली, 700 लीटर मूंगफली का तेल, 2,000 किलो आलू और 1,200 किलो चीनी, नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च वगैरह का इस्तेमाल किया गया है। इन सभी चीज़ों से कुल 13,000 किलो महाप्रसाद तैयार किया गया और भक्त इसे बड़ी श्रद्धा से खा रहे थे। सबका मालिक एक का महामंत्र देने वाले साईं बाबा के दर्शन के लिए सभी धर्मों के भक्त शिरडी आते हैं। उनमें से ज़्यादातर साईं संस्थान द्वारा चलाए जा रहे प्रसादालय में प्रसाद लेते हैं। आम तौर पर यहां दो सब्ज़ियां, चपाती और वरन-भात परोसा जाता है। वैसे, आषाढ़ी एकादशी और महाशिवरात्रि के दिन व्रत के मौके पर खास साबूदाने की खिचड़ी और झिरकाया प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है। साईं प्रसादालय के प्रमुख संजय शिंदे ने कहा, रविवार को शिरडी में करीब 70 हजार भक्तों द्वारा साईं खिचड़ी का लाभ उठाने का अनुमान है।

भारत-पाक सीमा पर गोलीबारी की आशंका के चलते पांच किमी आवाजाही पर रोक

कठुआ (एजेंसी)। सुरक्षा कारणों को देखते हुए संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट ने नया आदेश जारी करते हुए सीमावर्ती क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। जानकारी के अनुसार कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ पहाड़पुर से करोल कृष्णा तक 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों की गैर-जरूरी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन को खुफिया इनपुट मिला है कि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी समय सीमा पार गोलीबारी की आशंका है। इसी खतरे को देखते हुए ओल्ड सांबा-कठुआ मार्ग पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक भारी ट्रकों और टिपरों की आवाजाही भी प्रतिबंधित कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और कानून-व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीणों की सुरक्षा और किसी भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि को रोकने के लिए सीमावर्ती इलाकों में आवाजाही सीमित करना आवश्यक हो गया है। गौरतलब है कि हीरानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पिछले दो वर्षों से घुसपैठ की आशंका और ड्रोन गतिविधियों के कारण काफी संवेदनशील बनी हुई है, जिसके चलते स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये प्रतिबंध लागू किए गए हैं।

चंडीगढ़ को मिली इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, पीएम मोदी ने दिखाई वर्चुअली हरी झंडी

चंडीगढ़ (एजेंसी)। चंडीगढ़ के लोगों को रविवार को 25 नई इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मिला है। इन बसों को पीएम मोदी ने गुवाहाटी से वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है। ये बसें चंडीगढ़ को पीएमई बस सेवा योजना के तहत मिली हैं। इस दौरान चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद थे। प्रशासन का लक्ष्य अप्रैल तक शहर में कुल 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का टारगेट पूरा करना है। चंडीगढ़ के प्रशासन गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इन बसों के आने से शहर के यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन लोगों को बेहतर और प्रदूषण-मुक्त ट्रांसपोर्ट मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन नई बसों को हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर खास तौर पर डिजाइन किया गया है। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए खास सुविधाएं दी गई हैं ताकि उनका सफर आरामदायक हो सके। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन बसों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हर बस में पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा, जीपीएस सिस्टम के जरिए बसों की लोकेशन का भी पता लगाया जा सकेगा। सूत्रों के मुताबिक जो बसें पहले लंबे रूट से हटाई गई थीं, उन्हें फिर से लंबे रूट पर चलाने की तैयारी की जा रही है। इससे अंतरराज्यीय यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।

राजपाल यादव हैं जेल में और साल 2018 का वीडियो हो गया वायरल

-सलमान खान के साथ दिखा वीडियो, फैंस को लगा हो गए रिहा

मुंबई (एजेंसी)। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के तिहाड़ जेल में रहने की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं। चेक बाउंस केस में उन्हें जेल जाना पड़ा है, जिसके बाद कई बॉलीवुड सितारे उनकी मदद के लिए सामने आए हैं। इसी बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें वो रिहा होने की खुशी जता रहे हैं।

दरअसल सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें राजपाल यादव जेल से रिहा होने की खुशी जाहिर करते दिख रहे हैं और सलमान खान का धन्यवाद कर रहे हैं। वीडियो में राजपाल कहते हैं, सलमान भाई बड़े भाई की तरह हैं। उनके साथ बैठकर अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है। फैंस इस वीडियो को देखकर मान बैठे कि राजपाल यादव जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। दरअसल वायरल वीडियो साल 2018 का बताया जा है, क्योंकि वर्तमान में तो एक्टर अभी भी तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। राजपाल यादव पर साल 2010 का मामला दर्ज है। उन्होंने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और एक्टर कर्ज चुका नहीं पाए। कई चेक बाउंस होने के बाद उनका कुल कर्ज 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस कारण उन्हें जेल में बंद किया गया। राजपाल की इस मुश्किल घड़ी में कई बॉलीवुड सितारे सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन और सोनू सूद उनकी मदद को तैयार हैं। वायरल वीडियो के कारण फैन्स को भ्रम हुआ, लेकिन फिलहाल राजपाल यादव की रिहाई की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

सिक्किम और त्रिपुरा में लगे भूकंप झटके, तीव्रता कम होने से नहीं हुआ जान-माल का नुकसान

नई दिल्ली (एजेंसी)। रविवार सुबह भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में भूकंप के कई झटके लगे। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल चार झटके दर्ज किए गए, जिनमें से तीन सिक्किम और एक त्रिपुरा में आया। सिक्किम के नामची में सुबह 5:26 बजे और फिर 6:58 बजे 2.4 तीव्रता के दो झटके महसूस किए गए, जबकि मंगन में सुबह 5:10 बजे 2.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसके साथ ही त्रिपुरा के गोमती जिले में भी सुबह 6:38 बजे 2.6 तीव्रता का झटका आया। राहत की बात यह है कि इन झटकों की तीव्रता कम थी और केंद्र जमीन से केवल 5 से 10 किलोमीटर की गहराई में था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में सुबह 4:28 बजे 4.3 तीव्रता का सबसे तेज झटका महसूस आया, जिससे वहां हल्के नुकसान की खबरें है, हालांकि किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। इसके अलावा म्यांमार में तड़के दो बार 3.2 तीव्रता के झटके लगे। अमेरिका के ओक्लाहोमा, इंडोनेशिया के जावा, चिली और पुर्तगाल के अजोरेस द्वीप समूह में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सीस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक पुर्तगाल में आए भूकंप की तीव्रता 2.6 मापी गई। विशेषज्ञों के मुताबक रविवार को आए इन झटकों से कहीं भी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। सिक्किम और त्रिपुरा में आए भूकंप के झटके हल्के थे, जिनसे जनजीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। हालांकि, वैश्विक स्तर पर भूकंप हमेशा एक बड़ी चिंता का विषय है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया भर में भूकंपों के कारण हर साल औसतन 40 से 60 अरब डॉलर यानी करीब 3 से 5 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है। 2011 में जापान का तोहोकू भूकंप और 2023 में तुर्की-सीरिया में आई तबाही इसके भयावह उदाहरण हैं। बता दें सालाना आधार पर भूकंप के कारण औसतन 10,000 से 20,000 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन यह संख्या आपदा की तीव्रता के आधार पर बदलती रहती है। जानकारों का कहना है कि अक्सर भूकंप खुद उतना खतरनाक नहीं होता, जितना कि कमजोर इमारतों का गिरना, आग लगना, सुनामी या भूस्खलन नुकसान पहुंचाते हैं।

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र कल से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, रक्षा सहयोग को मजबूत करने करेंगे चर्चा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 16 से 19 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग को और मजबूत करना और दोनों देशों के बीच बढ़ते तालमेल को सुदृढ़ करना है। अपनी सेना प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ व्यापक वार्ता करेंगे, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास, पेशेवर आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण समेत सेना-से-सेना के बीच संबंधों को बढ़ाना है। सिडनी में सेना प्रमुख (सीओएएस) फोर्सेस कमांड (एफओआरकॉमडी), स्पेशल ऑपरेशंस कमांड (एसओकॉमडी) और द्वितीय डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। यह उल्लेखनीय है कि द्वितीय डिवीजन के सैनिक द्विपक्षीय सेना अभ्यास ऑस्ट्राहिंद में भाग लेते हैं, जिसका अगला संस्करण 2026 में भारत में आयोजित होने वाला है। सेना प्रमुख उपेंद्र कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट के साथ बातचीत होगी। ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख और जनरल उपेंद्र द्विवेदी, यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के 2015 बैच

के पूर्व छात्र हैं और उनके बीच मजबूत पेशेवर संबंध हैं। इसके अलावा जनरल उपेंद्र संयुक्त संचालन कमान मुख्यालय (एचक्यूजेओसी) का दौरा करेंगे, जहां वे संयुक्त संचालन कमांडर से मिलेंगे और एकीकृत और बहु-क्षेत्रीय अभियानों समेत ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों की परिचालन गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेना प्रमुख शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और बलिदान एवं सेवा की साझा विरासत का सम्मान करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय रक्षा दिग्गजों से भी मुलाकात करेंगे, जो भारतीय सशस्त्र बलों और उसके दिग्गजों के बीच अटूट बंधन को रेखांकित करता है। यह दौरा रक्षा सहयोग को और बढ़ाने तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा में संयुक्त रूप से योगदान देने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

ममता बनर्जी ने तारिक भाई को भेजा फूल और मिठाइयां, रमजान की अग्रिम मुबारकबाद

-रहमान 17 फरवरी को लेंगे शपथ

कोलकाता (एजेंसी)। बांग्लादेश की राजनीति में बड़े बदलाव के तौर पर तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने 13वें संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पार्टी को दो-तिहाई बहुमत मिलने के बाद तारिक रहमान 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह के लिए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाई रहमान को वधाई देने के साथ ही फूलों का गुलदस्ता और मिठाइयां भेजकर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

तारिक रहमान को मिली शानदार जीत के बाद पड़ोसी भारत समेत अनेक देशों ने उन्हें बधाई प्रेषित की है। यहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तारिक रहमान को फूलों का गुलदस्ता और मिठाइयाँ भेजकर अपनी शुभकामनाएँ दी हैं। बीएनपी चेयरमैन के राजनीतिक कार्यालय की ओर से जारी बयान में बताया गया, कि शनिवार को गुलशन स्थित कार्यालय में बीएनपी मीडिया सेल सदस्य अतिउर रहमान रुमन ने सीएम ममता बनर्जी की ओर से भेजे गए उपहार को प्राप्त किया। इससे एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर तारिक रहमान को 'तारिक भाई' संबोधित करते हुए चुनावी जीत की बधाई दी थी। उन्होंने अपने संदेश में बांग्लादेश की जनता को शुभकामनाएँ देते हुए अग्रिम रमजान की मुबारकबाद भी दी। ममता बनर्जी ने लिखा कि यह जीत लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है और इससे क्षेत्रीय सहयोग को नई दिशा मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी का यह कदम केवल औपचारिक बधाई नहीं, बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक रिश्तों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव रहा है, ऐसे में यह पहल द्विपक्षीय संबंधों में नई गर्माहट ला सकती है।

गौरतलब है कि तारिक रहमान दिसंबर 2025 में 17 वर्षों के निर्वासन के बाद लंदन से स्वदेश लौटे थे। उनकी वापसी और अब चुनावी विजय को उनके राजनीतिक जीवन का बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। चुनाव परिणामों के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस समेत कई अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी है। अब सबकी नजरें 17 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हैं, जिसे बांग्लादेश की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

जमानत के मिलने के बाद बार-बार नई एफआईआर करना कानून का दुरुपयोग : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली(एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी आरोपी को अदालत से जमानत मिल जाती है, तो उसे जेल में रखने के लिए बार-बार नई एफआईआर दर्ज करना कानून का दुरुपयोग है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह तरीका मौलिक अधिकार के तहत सीधे हस्तक्षेप की मांग करता है। यह मामला झारखंड का है। 20 मई 2025 को रांची के एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने 1988 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की थी। इसी मामले में आरोपी से पूछताछ चल रही थी, तभी एसीबी हजारीबाग ने 2010 में कथित वन भूमि के म्यूटेशन से जुड़े मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज कर दी। यह मामला करीब 15 साल पुरानी घटना से जुड़ा था। इसके बाद 2025 में दो और एफआईआर दर्ज की गई।

ओवैसी का बड़ा बयान: वफादारी साबित करने के लिए वंदे मातरम का सहारा जरूरी नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रगीत और देश के प्रति वफादारी को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है। एक हालिया इंटरव्यू के दौरान ओवैसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वंदे मातरम गाना या इसे सम्मान देना किसी भी नागरिक की देश के प्रति वफादारी का पैमाना नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये संगठन भारत को एक धार्मिक राष्ट्र में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी ने तर्क दिया कि भारतीय संविधान हम लोग शब्द से शुरू होता है, न कि भारत माता की जय जैसे नारों से। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि यह देश के हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता के बुनियादी अधिकार की गारंटी देता है।

यह विवाद तब गहराया जब केंद्र सरकार ने 12 फरवरी को एक नया आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान ही सम्मान देना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार, अब राष्ट्रगीत के सभी छह अंतरों का गायन अनिवार्य होगा, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड निर्धारित की गई है। इससे पहले तक आमतौर पर मूल गीत के केवल पहले दो अंतरे ही गाए जाते थे। ओवैसी ने अपने संबोधन में सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की भी तीखी आलोचना की। उन्होंने जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आयोग ने सावरकर को महात्मा गांधी की हत्या का साजिशकर्ता माना था। इसके अलावा, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कयामत शब्द के इस्तेमाल पर भी कटाक्ष किया। ओवैसी ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को कम से कम एक उर्दू शब्द का हिंदी अर्थ पता होना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए ओवैसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े किसी भी अविश्वास प्रस्ताव में अपनी भूमिका से साफ इनकार किया। तेलंगाना की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा जिस तरह उनका नाम लेती है, उससे लगता है कि वे उन्हें काफी पसंद करते हैं।

भारत के खिलाफ साजिश, मौत की सजा पाने वाले तीन अपराधी बने सांसद

-मुहम्मद यूनुस ने इन पर लगे आरोप हटा दिए थे, अब बांग्लादेश की संसद में बैठेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। बांग्लादेश में आम चुनाव में दिवंगत पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने भारी जीत हासिल की है। इस चुनाव में तीन नेता ऐसे भी हैं, जो बहुत ही भाग्यशाली रहे। इनमें दो नेता बीएनपी के और एक जमात-ए-इस्लामी से हैं। बीएनपी के लुत्फेज्जमां बाबर, अब्दुस सलाम पिंटू और जमात के अजहरुल इस्लाम इन तीनों पर गंभीर आरोप हैं। हालांकि मुहम्मद यूनुस ने इन पर लगे सभी आरोपों को हटा दिया था। अब ये तीनों बांग्लादेश की संसद में बैठेंगे।

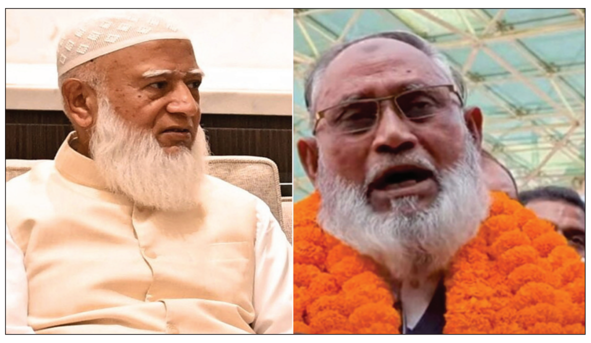

बता दें दिसंबर 2024 में बांग्लादेश हाई कोर्ट ने तारिक रहमान, लुत्फोज्जमां बाबर और दूसरे लोगों को बरी कर दिया था। इन लोगों को 21 अगस्त 2004 को शेख हसीना को टारगेट करके किए गए ग्रेनेड हमले से जुड़े दो मामलों में दोषी ठहराया था। हालांकि वह बाल-बाल बच गईं, लेकिन इस हमले में 24 लोग मारे गए थे। लुत्फोज्जमां बाबर ने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी को 1.6 लाख वोटों से हराया। इसके अलावा अब्दुस सलाम पिंटू करीब 2 लाख वोटों से जीत हासिल की है। ये वही पिंटू है जिसे ग्रेनेड अटैक मामले में बरी किया गया। इतना ही नहीं पिंटू पर पाकिस्तान के टेरर ग्रुप हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (हूजी) का समर्थन करने का आरोप था, जो भारत में हमलों के पीछे था। इसमें 2006 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक कोर्ट परिसर में, 2007 में अजमेर शरीफ दरगाह और 2011 में दिल्ली में हुए धमाके में शामिल था।

रिपोर्ट के मुताबिक 1971 के लिबरेशन वॉर में 1,200 से ज्यादा लोगों की मौत के लिए इस्लाम जिम्मेदार था। वह रेप के 13 मामलों में भी आरोपी है। इन सभी जुर्मों के लिए उसे 2014 में मौत की सजा दी गई थी, लेकिन यूनुस ने उसे माफ कर दिया और सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इन तीनों नेताओं को मौत की सजा सुनाई गई, थी लेकिन यूनुस ने इन्हें माफ कर दिया और अब ये बांग्लादेश की संसद में बैठे नजर आएंगे।

मौसम में बड़ा बदलाव: पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट और मैदानों में गर्मी की दस्तक

देहरादून (एजेंसी)। देश के मौसम में इन दिनों विरोधाभासी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जहां पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय दो नए पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है, वहीं मध्य भारत के मैदानी इलाकों में पारा तेजी से चढ़ने लगा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, 13 से 16 फरवरी के बीच सक्रिय हुए इन विक्षोभों का असर अगले दो दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी के रूप में दिखाई देगा।

मैदानी राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 16 फरवरी से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। राजस्थान के जयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों के साथ-साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई गई है। इस नए मौसमी तंत्र का सर्वाधिक प्रभाव 17 और 18 फरवरी को देखने को मिलेगा। इसके विपरीत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में गर्मी ने दस्तक दे दी है। भोपाल और इंदौर समेत मध्य प्रदेश के 17 शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, हालांकि पचमढ़ी और खजुराहो जैसे इलाकों में रातें अब भी ठंडी बनी हुई हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पारा 32.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, जो सामान्य से अधिक है। पहाड़ी राज्यों में स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। उत्तराखंड के पांच जिलों-उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 16 फरवरी को बर्फबारी का अलर्ट है। यहां मुनस्यारी में तापमान गिरकर -28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि बद्रीनाथ और गंगोत्री में भी पारा -20 डिग्री से नीचे बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में दिन के तापमान में करीब 7 डिग्री का असामान्य उछाल देखा गया, लेकिन 16 फरवरी से लाहौल-स्पीति और किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर से बर्फ की सफेद चादर बिछने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, 16 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश में आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे पूर्वोत्तर भारत के तापमान में भी गिरावट आ सकती है।